

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/आषाढ़ 9, 1937 No. 175] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ASADHA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

अंतिम जांच परिणाम

विषय: कोरिया जन. गण. में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनिट्राइल ब्टाडिन रबड़ (एन बी आर) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की अंतिम समीक्षा (एस एस आर) के संबंध में।

सं. 15/29/2013-डी जी ए डी.—सीमा शुल्क अधिनियम 1975, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संकलन तथा हानि का निर्धारण हेतु) नियमावली 1995 (इसके बाद नियमावली के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में।

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. जबिक, कोरिया जन. गण. और जर्मनी में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन रबइ अथवा एन बी आर (इसके बाद संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित) आयात के संबंध में मूल जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद प्राधिकारी के रूप में भी संदर्भित) द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1996 की अधिसूचना संख्या 9/1/95-एडीडी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रारंभिक जांच परिणाम इस प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 दिसंबर, 1996 की अधिसूचना संख्या 9/1/95-एडीडी के द्वारा जारी किया गया था और अनंतिम पाटन रोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या 9/97-सीमा शुल्क के द्वारा लगाया गया था। अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना इस प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 1997 की अधिसूचना संख्या 9/1/95-एडीडी के द्वारा जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में इस प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क

2900 GI/2015 (1)

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1997 की अधिसूचना संख्या 62/1997-सीमा शुल्क के द्वारा कोरिया जन. गण. तथा जर्मनी में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाया गया था।

- उबिक, प्राधिकारी ने कोरिया जन. गण. तथा जर्मनी में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 50/1/2001 के द्वारा लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की प्रथम अंतिम समीक्षा शुरू की और दिनांक 21 सितंबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 50/1/2001 के द्वारा संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगातार लगाये रखने की सिफारिश की। राजस्व विभाग में केंद्र सरकार ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 111/2002- सीमा शुल्क के द्वारा कोरिया जन. गण. तथा जर्मनी में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क लगातार लगाये रखना अधिसूचित किया।
- 4. प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च, 2004 को कोरिया जन. गण. तथा जर्मनी से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मध्याविध समीक्षा जांच शुरू की और दिनांक 6 जून, 2005 की अधिसूचना संख्या 15/5/2004 के द्वारा संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगातार लगाये रखने की सिफारिश की। पाटन रोधी शुल्कों को लगातार लगाये रखना दिनांक 1 सितंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 78/2005- सीमा शुल्क के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- एक अन्य अंतिम समीक्षा जांच इस प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/6/2007 के द्वारा शुरू की गई थी और प्राधिकारी ने केवल कोरिया जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को लगातार लगाये रखने की सिफारिश दिनांक 4 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/6/2007 के द्वारा की और दिनांक 2 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 01/2009- सीमा शुल्क के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लगातार शुल्क अधिसूचित लगाया गया था।
- 6. जबिक, वर्तमान एस एस आर जांच में मैसर्स ओमनोवा सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. ने कोरिया जन. गण. (इसके बाद संबद्ध देश के रूप में भी संदर्भित) में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने तथा घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप हानि होने की संभावना का आरोप लगाते हुए इस अधिनियम और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर इस प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया और कोरिया जन. गण. में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए समीक्षा का अन्रोध किया है।
- 7. पाटन रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पिठत इस अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार तथा घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किये गये विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए प्राधिकारी ने दिनांक 31 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 15/29/2013- डी जी ए डी के द्वारा संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में शुल्कों को लगातार लगाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा इस बात की जांच करने के लिए कि इस प्रकार के शुल्क के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने अथवा उसके बारबार होने और घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है, वर्तमान अंतिम समीक्षा जांच शुरू की। संबद्ध देश से संबंध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क की वैधता केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 06/2014-सीमा शुल्क (ए डी डी) के द्वारा 1 जनवरी, 2015 तक बढ़ाया गया है।

8. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पूर्व की जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

- 9. नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है :
 - (क) नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावास को नियम 6(2) के अनुरूप इन जांचों को शुरू करने के संबंध में सूचित किया गया था।
 - (ख) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुरूप संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात निर्यातकों को इस आवेदन का अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति भी सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध करायी गयी थी और इसे जहां भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया था।
 - (ग) प्राधिकारी ने कोरिया जन. गण. के निम्निलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों (जिनके नाम व पते इस प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें नियमावली 6(2) और 6(4) के अनुरूप पत्र की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने का अवसर दिया :
 - (i) मैसर्स क्म्हो पैट्रोकेमिकल कं. लिमि.
 - (ii) मैसर्स एल जी केम लिमि.
 - (घ) संबद्ध देश से उत्पादकों/ निर्यातकों दोनों से निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त हुआ था।
 - (ङ) प्राधिकारी ने भारत में संबद्घ वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं (जिनके नाम व पते इस प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे) को आम सूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें नियमावली 6(4) के अनुरूप पत्र के जारी होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने की सलाह दी:
 - (i) न्-र्कोक प्रॉडक्ट प्रा. लि.
 - (ii) शक्तिमान रब रोल्स प्रा. लि.
 - (iii) बोनी पालीमर्स लि.
 - (iv) यूनिक रबड़ उद्योग
 - (v) लखानी रबड़ उदयोग लि.
 - (vi) अलस्का टायर्स प्रा. लि.
 - (vii) स्पर सील (इंडिया) लि.
 - (viii) रूप रबड़
 - (ix) लयालप्र रबड़ मिल्स
 - (x) फेरोलिट ज्वाइंटिंग लि.
 - (xi) गेट्स इंडिया प्रा. लि.
 - (xii) बनको प्रॉडक्टस (इंडिया) लिमि.
 - (xiii) भारत कोरब इंडस्ट्रीज
 - (xiv) चैम्पियन ज्वाइंटिंग लि.
 - (xv) फेवरिट सेफ्टी प्रॉडक्ट्स
 - (xvi) ग्रिंटबैक
 - (xvii) इंडस्ट्रियल रोलर कोरपोरेशन
 - (xviii) लाठिया इंड. स्पलायर्स कं. प्रा. लि.

- (xix) पोलीरब एक्स्ट्रक्शन (इंडिया)
- (xx) प्रेसिटेक्स रबड़ इंडिया प्रा. लि.
- (xxi) आंध्रा पोलीमर्स (प्रा.) लि.
- (xxii) गोदावरी पेट्रो प्रॉडक्स (प्रा.) लि.
- (xxiii) गेलेक्सी रबड़ प्रॉडक्स
- (xxiv) स्ंदरम इंडस्ट्रीज लि.
- (xxv) स्ंदरम ब्रेकलाइन लि.
- (xxvi) स्ंदरम ऑटो कोम्पोनेंट लि.
- (xxvii) सुजा रबड़ इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
- (xxviii) राने ब्रेकलिंगगिंग लि.
- (xxix) एम आर एफ लिमि.
- (xxx) लक्ष्मी मेकेनिक वर्क लि.
- (xxxi) इडस्ट्रियल रबड़ प्रॉडक्स
- (xxxii) हबासिट लाकोला प्रा. लि.
- (xxxiii) इल्गी अल्ट्रा इंडस्ट्रिज लिमि.
- (xxxiv) भैसर्स इम्पेरियल रबड़ प्रॉडक्स
- (xxxv) मैसर्स जयाश्री पोलीमर्स प्रा. लि.
- (xxxvi) मैसर्स के. डी. जोशी
- (xxxvii) मैसर्स प्रफेक्ट ऑयल शील्स एंड आई. आर. पी.
- (xxxviii) भैसर्स हिन्द्स्तान कम्पोजिट्स लि.
- (xxxix) भैसर्स इनएकोरा लि.
- (xl) मैसर्स इम्पीरियल वॉटरप्रूफिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
- (xli) भैसर्स पाकर मार्कवेल इंड. प्रा. लि.
- (च) किसी आयातक/ प्रयोक्ता द्वारा आयातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (छ) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन से जांच की अविध (पी ओ आई) 1 अक्टूबर, 2012 से 30 सितंबर, 2013 थी। हानि के विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 2010 मार्च 2011, अप्रैल 2011 मार्च 2012, अप्रैल 2012 मार्च 2013 की जांच की अविध और इस जांच की अविध को शामिल किया।
- (ज) घरेलू उद्योग ने आयातों के लिए डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर विश्वास किया था। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से जांच की अविध और जांच के अविध के बाद को भी शामिल करते हुए हानि की अविध के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, जांच की अविध के लिए, प्राधिकारी ने सहयोग करने वाले निर्यातकों के सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया था क्योंकि उसकी मात्रा और मूल्य अपेक्षाकृत अधिक पाए गये थे।

- (झ) निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस जांच से संबंधित सूचना न तो दी है और न ही प्राधिकारी को कोई उत्तर दिया है, को इस प्राधिकारी द्वारा गैर-सहयोगी हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।
- (ञ) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया था।
- (ट) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और हानि रहित मूल्य का निर्धारण करने के लिए पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-।।। में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर यथा संभव जांच की है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली हानि से बचाने के लिए पर्याप्त होगा।
- (ठ) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुरूप, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 9 अक्टूबर, 2014 को आयोजित आम सुनवाई जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार उपस्थित हुए थे, में मौखिक रूप से अपने विचार रखने का अवसर भी दिया। इन पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने दृष्टिकोण को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
- (इ) जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और इस प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अन्रोध की जांच की गई और उसका समाधान इस निष्कर्ष में किया गया है।
- (ढ) राजस्व विभाग ने दिनांक 8 जनवरी 2015 के अपने पत्र संख्या 354/179/2002-टी आर यू (भाग **V**) के द्वारा जांच को पूरा करने के लिए इस समयाविध को 30 जनवरी, 2015 तक बढ़ा दिया।
- (ण) घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सूचना और आंकड़ों का मौके पर सत्यापन उस हद तक किया गया जहां तक इसे आवश्यक समझा गया।
- (त) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में विचार किया गया और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करें।
- (थ) जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है अथवा अन्य प्रकार से नहीं दिया है अथवा पर्याप्त रूप से इस जांच में बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने 'उपलब्ध तथ्यों' के आधार पर इन निष्कर्षों को रिकार्ड किया है और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है।
- (द) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुरूप प्राधिकारी द्वारा 22 जून, 2015 को जारी प्रकटन वक्तव्य के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को आवश्यक तथ्यों की जानकारी दी गई और उसके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत माने जाने की सीमा तक इस निष्कर्ष में विचार किया गया है और उसका समाधान किया गया है।
- (ध) इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा ऐसा माने जाने को इंगित करता है।

(न) जांच की अविध के लिए विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा 56.89 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ग. निहित मुकदमा

10. डी जी ए डी द्वारा वर्तमान एस एस आर जांच को शुरू करने और डी ओ आर द्वारा संबंधित पाटन रोधी शुल्क की वैधता का विस्तार किए जाने को कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कं. लिमि. और फेयर डील पोली कैम्प लिमि. द्वारा क्रमश: डब्ल्यू पी सी सं. 1851/2014 और सं. 1866/2014 के द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 जुलाई, 2014 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को वैध ठहराया था।

"धारा १ क (5) के दूसरे परंतुक की आदेशात्मक प्रवृत्ति संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि यदि केंद्र सरकार अंतिम समीक्षा अविध के दौरान करारोपण को बढ़ाना चाहती है तब इसे उस प्रावधान के संबंध में अनुपालन करना है और उसे मूल अविध के समाप्त होने के पूर्व करना है - जो इस मामले में 1.1.2014 थी। ऐसा नहीं किए जाने पर, 23.1.2014 की बाद की अधिसूचना के माध्यम से शुल्क लगाने के इसके प्रयास को कानून का अधिकार प्राप्त नहीं है; यह धारा १ क (5) के परंतुक की शर्तों के प्रतिकृत है। इस कारण से" किसी भी राशि को वसूलने का प्रयास भारत के संविधान के अनुच्छेद के 265 का उल्लंघन करता है। 27। उपर्युक्त निष्कर्षों को देखते हुए यह माना जाता है कि अंतिम समीक्षा शुरू करना वैध और कानूनी है; हालांकि 23.1.2014 की अधिसूचना जिसे चुनौती दी गई है, के माध्यम से पाटन रोधी शुल्क लगाने को कानून का अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त अधिसूचना को गैर कानूनी घोषित किया जाता है और एतदद्वारा रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को यह हक है कि वह आज की तारीख तक भुगतान की गई राशियों की वापसी का दावा करें। रिट याचिकाएं आंशिक रूप से सफल होती हैं और इन्हें उपर्युक्त सीमा तक अनुमित दी जाती है; लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।"

11. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के उपर्युक्त निर्णय को इस प्राधिकारी द्वारा 2014 की एस एल पी सं. 29268-69 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9 मार्च, 2015 के अपने अंतरिम आदेश के माध्यम से उपर्युक्त निर्णय पर रोक लगा दी है।

घ. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र

घरेलू उत्पाद द्वारा अनुरोध

- 12. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन रबड़ (एन बी आर) है। विचाराधीन उत्पाद वही है जिसे मूल और बाद की जांचों में परिभाषित किया गया है।
 - (ii) एन बी आर का उपयोग प्राथमिक रूप से किया जाता है जहां तेल का प्रतिरोध, घर्षण का प्रतिरोध और ताप के प्रतिरोध के उपयोग शामिल होते हैं। एन बी आर का व्यापक रूप से उपयोग रक्षा, ऑटोमोबाइल, फुटवियर, फैब्रिक्स, प्रिंटर, ऑयल फील्ड उत्पाद, उद्योगों आदि में किया जाता है।
 - (iii) एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन रबड़ की श्रेणियों का विवरण एक्रीलोनिट्राइल के पदार्थ और रबड़ में मूनी विस्कोसिटी के संबंध में किया जाता है। एन बी आर में एक्रीलोनिट्राइल और मूनी विस्कोसिटी की प्रतिशत मात्रा एन बी आर की एक श्रेणी में अन्य श्रेणी से अलग होता है। भारतीय उद्योग संबद्ध देश से वर्तमान में आयात किए जा रहे विभिन्न श्रेणियों के समतुल्य/ तुलनीय पदार्थों का उत्पादन करता है।

- (iv) पी यू सी एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन रबड़ (एन बी आर) है जिसे नाइट्राइल रबड़ के रूप में भी जाना जाता है और यह उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की प्रथम सूची के अध्याय 40 तथा आई टी सी एच एस वर्गीकरण में शीर्ष संख्या 40025900 के अंतर्गत आता है। हालांकि, सीमा शुल्क का वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और इस जांच के क्षेत्र पर यह बाध्यकारी नहीं है।
- (v) याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से निर्यातित संबंध वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में भौतिक और रासायनिक लक्षणों, निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और उद्योग, उत्पाद का विनिर्देशन, मूल्य, वितरण और विपणन और इन सामानों का शुल्क वर्गीकरण जैसे मानदण्डों के संबंध में तुलनीय लक्षण होते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं इस नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

13. किसी भी उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) तथा समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पूर्व की जांचों तथा वर्तमान अंतिम समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) कोरिया जन. गण. में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन रबड़ (एन बी आर) है। एन बी आर एक्रीलोनिट्राइल (ए सी एन) और बूटाडिन का एक सिंथेटिक रबड़ सह पोलीमर है। एन बी आर का उपयोग विभिन्न रबड़ वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जहां तेल, घर्षण और ताप के उपयोग के प्रति प्रतिरोध शामिल होता है, जैसे ऑयल शील्स, हौज, ऑटोमोटिव उत्पाद, गैस किट, चावल की भूसी अलग करने वाले रोल्स, प्रिंटर, फैब्रिक्स, ऑयल फील्ड उत्पाद आदि। एन बी आर के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्चा माल एक्रीलोनिट्राइल और बूटाडिन हैं। एन बी आर की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा मूनी विस्कोसिटी और एक्रीलोनिट्राइल मात्रा के संबंध में दी जाती है। एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन रबड़ (एन बी आर) का वर्गीकरण उप-शीर्ष सं. 40025900 के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 40 में दिया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क का वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। चूंकि वर्तमान जांच एक अंतिम समीक्षा है अतः पी यू सी वहीं है जो पूर्व की जांच में था।

ङ. <u>घरेलू उद्योग और उसका स्थान</u>

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 15. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र तथा उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - (i) याचिकाकर्ता अर्थात ओमनोवा सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. इस देश में एन बी आर का एकमात्र उत्पादक है। इस प्रकार से ओमनोवा सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. द्वारा एन बी आर का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत होता है।
 - (ii) उसको देखते हुए ओमनोवा सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. वर्तमान याचिका दायर करने के लिए स्थान की आवश्यकता को पूरा करता है और इस नियमावली के आशय के भीतर 'घरेलू उद्योग' है।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

16. किसी भी उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के स्थान और कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई अन्रोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान है :
 - "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।
- 18. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्तमान अंतिम समीक्षा के लिए आवेदन मैसर्स ओमनोवा सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो इस देश में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र घरेलू उत्पादक है। मैसर्स ओमनोवा सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. ने यह भी घोषणा की है कि उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी संबद्ध कम्पनी के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात कोरिया जन. गण. से नहीं हुआ है। वे भारत में किसी आयातक अथवा कोरिया जन. गण. के किसी निर्यातक से नहीं जुड़े हैं। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए तथा पाटन रोधी नियमावली के संबंध में प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि मैसर्स ओमनोवा सॉल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. नियम 2 (ख) के तात्पर्य के अधीन घरेलू उद्योग है और यह पाटन रोधी नियमावली के नियम 5(3) के संबंध में स्थान के मानदण्ड को पूरा करता है।

च. विविध मुद्दे

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

- 19. किसी भी उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किया गया है :
 - वर्तमान अंतिम समीक्षा शुरू करना कानून की दृष्टि से गलत है। संबद्ध वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क 1 जनवरी, 2014 को समाप्त हो गया और दिनांक 23 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से शुल्क का विस्तार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी माना गया है। याचिकाकर्ता ने शुल्क के विस्तार के लिए पर्याप्त आधार भी सिद्ध नहीं किए हैं। प्रतिवादी इस जांच में इस विरोध के आधार पर भाग ले रहे हैं कि कोई पाटन रोधी शुल्क लागू नहीं है। वर्तमान जांच मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों के समाप्त होने के बाद अनुचित ढंग से शुरू की गई थी और यह प्रारंभ में ही समाप्त किए जाने के लायक था।
 - गट्यपि, प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की तिथि 31 दिसंबर, 2013 है हालांकि, अंतिम समीक्षा को प्रारंभ करने संबंधी सूचना प्रकाशित की गई थी अथवा अन्य शब्दों में 6 जनवरी, 2014 को ही सार्वजनिक की गई थी। पाटन रोधी शुल्क को बढ़ाने की शक्ति इस अधिनियम की धारा 9क (5) में दूसरे परंतुक के रूप में केंद्र सरकार के पास है; हालांकि इस मामले में इस शुल्क के समाप्त होने के 2 महीने बाद तक ऐसा कोई विस्तार जारी नहीं किया गया था।
 - III. डी जी ए डी द्वारा जारी एक स्पष्ट आदेश के बावजूद की घरेलू उद्योग जो अंतिम समीक्षा प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं, को पाटन रोधी शुल्कों के समाप्त होने के कम से कम 90 दिन पूर्व एक विधिवत प्रमाणित अनुरोध दायर करना चाहिए, याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच में 11 नवंबर, 2013 को अंतिम समीक्षा प्रारंभ करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की है जो डी जी ए डी द्वारा स्वीकृत 90 दिन की समय सीमा के बाद दी गई है। अतः प्राधिकारी को तत्काल वर्तमान अंतिम समीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए।

- IV. पाटन रोधी शुल्क 16 वर्षों से अधिक से कोरिया के विरुद्ध लागू है। चीन जन. गण. से "ड्राई सैल बैटरी" के आयातों के संबंध में डी जी ए डी का अपने एस एस आर अंतिम जांच परिणामों में दृष्टिकोण के अनुरूप की पाटन रोधी शुल्क सामान्य तौर पर 10 वर्षों के बाद जारी नहीं रखा जाना चाहिए। कोरिया से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क को हटा दिया जाना चाहिए।
- V. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाटन रोधी शुल्क का विस्तार करने कि सीमा शुल्क की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। कुम्हों ने पहले ही जांच प्रारंभ करने को वैध ठहराने के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए एक एस एल पी दायर की है। अत: वर्तमान अंतिम समीक्षा प्रारंभ करना गैर कानूनी है और इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
- VI. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय डी जी ए डी पर बाध्यकारी है और डी जी ए डी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस तथ्य को देखते हुए कि (क) कोई पाटन रोधी शुल्क मौजूद नहीं है क्योंकि विस्तार संबंधी अधिसूचना दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी माना गया है और (ख) प्रमुख अधिसूचना भी समाप्त हो गई है, इस प्रकार डी जी ए डी किसी प्रकार का निर्धारण नहीं कर सकता है कि "उक्त पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को हानि और पाटन के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना है"। चूंकि पाटन रोधी शुल्क पहले ही समाप्त हो चुका है अतः डी जी ए डी नियम 23 के संबंध में कोई अन्य निर्धारण नहीं कर सकता है।
- VII. आवेदक को लगभग 17 वर्षों से पाटन रोधी शुल्क की सुरक्षा प्राप्त होती रही है। आवेदक इस स्थिति पर पहुंच गया है जिसमें पाटन रोधी शुल्क पर यह पूर्ण रूप से निर्भर है और हमेशा निर्भर रहेगा। ऐसी स्थिति होने पर जहां आवेदक अंतरनिहित रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, इसे आयातकों और अन्य अंतिम प्रायोक्ताओं को प्रभावित किए बिना किसी अन्य प्रकार से संरक्षण लेने की कोशिश करनी चाहिए।

घरेल् उद्योग द्वारा अनुरोध

- 20. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :
 - यह तर्क कि केंद्र सरकार मौजूदा शुल्कों और संशोधित शुल्कों के बीच अंतर को देखते हुए अंतिम जांच परिणाम प्राप्त होने पर पाटन रोधी शुल्क का विस्तार करने की स्थिति में नहीं होगी, सही नहीं है। धारा 9क (5) में स्पष्ट रूप से शुल्क के समाप्त होने के पूर्व और न कि "समाप्त होने के बहुत पहले" इस जांच को शुरू करने का प्रावधान है।
 - ii माननीय उच्च न्यायालय ने जांच प्रारंभ करने को सही ठहराया है और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणाम को रिकार्ड पूर्णतः न्यायोचित रूप से किया है।
 - iii यह तर्क कि घरेलू उद्योग को एक लंबी अविध से संरक्षण मिलता रहा है संगत नहीं है। सबसे पहले पाटन रोधी शुल्क लगाना "संरक्षण" नहीं है। पाटन रोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य, यिद वह घरेलू उद्योग को हानि पहुंचा रहा है अथवा इससे हानि होने की संभावना है तब पाटन की अनुचित प्रथा को समाप्त करना मात्र है। शुल्क तब तक लागू रहना चाहिए जब तक पाटन जो हानि पहुंचा रहा है, का मुकाबला करने के लिए इसे आवश्यक माना जाता हो।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

21. विविध अन्रोध की जांच नीचे दिए अन्सार की गई है :

परस्पर विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान अंतिम समीक्षा शुरू करना कानून की दृष्टि से गलत है और इसे प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि 31 दिसंबर, 2013 की आरंभ करने संबंधी अधिसूचना 6 जनवरी, 2014 को सार्वजनिक की गई थी और दिनांक 11 जुलाई, 2014 के माननीय दिल्ली उच्च के निर्णय में शुल्क के विस्तार को गैर कानूनी माना गया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पहले ही प्रारंभन को वैध और कानूनी माना है; लेकिन पाटन रोधी शुल्क को लगाने को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को इस प्राधिकारी द्वारा तथा घरेलू उद्योग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 9 मार्च, 2015 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा उक्त निर्णय पर रोक लगा दी है। इस प्रकार से इस तर्क का कोई आधार नहीं है।

ां परस्पर विरोधी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने दिनांक 6.6.2011 के व्यापार सूचना संख्या 2/2011 के संबंध में पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की तिथि से 90 दिन पूर्व के भीतर याचिका दायर नहीं की है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी नियमावली के नियम 23(1) (ख) के प्रावधानों में निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह उस अविध के समाप्त होने के पूर्व समय की उचित अविध के भीतर पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा और विस्तार के लिए प्राप्त याचिका पर विचार करें। इस नियमावली के अंतर्गत दिए गए समय की अपेक्षा की उचित एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य प्राधिकारी को किसी आवेदन पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय देना है और न कि प्राधिकारी को उस अविध के बाद किसी आवेदन पर विचार करने से रोकना है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन दायर करने में विलंब के तथ्यों की जांच इस प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करते समय की गई थी। यह तथ्य की जांच इस प्राधिकार शुरू कर दी गई है इस बात को मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि विलंब को प्राधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है।

यह तर्क कि पाटन रोधी शुल्क 16 वर्षों से अधिक से कोरिया के विरुद्ध लागू है इसिलए इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, का कोई कानूनी आधार नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम अथवा पाटन रोधी नियमावली अथवा डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण किया गया हो। जब तक घरेलू उद्योग को पाटन से हानि हो रही हो, पाटन रोधी शुल्क लागू रह सकते हैं तािक घरेलू उद्योग पािटत वस्तुओं की तुलना में समान अवसर प्रदान किया जा सके।

छ. <u>गोपनीयता</u>

iii

<u>निर्यातकों/ आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध</u>

- 22. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
 - i वर्तमान याचिका में अत्यधिक गोपनीयता की खामी है।
 - ii लेन-देन वार आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। आयात आंकड़ों के बिना यह संभव नहीं है कि सटीकता के साथ इस बात का निर्धारण किया जाये कि क्या आयात के प्रभावों के संबंध में दावे सही ढंग से दिये गये हैं, अथवा नहीं।

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

- 23. घरेलू उद्योग गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :
 - i निर्यातकों ने उनके द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है।
 - ii प्रतिवादी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दावा किया गया अत्यधिक गोपनीयता पूर्ण रूप से घरेलू उद्योग को अपने हितों की रक्षा करने से रोकता था।
 - iii घरेलू उद्योग द्वारा इस प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया अगोपनीय लेन-देन वार डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़े सार्वजनिक फाइल में दिए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किये गये अनुरोध और इस प्राधिकारी द्वारा माने गये संगत अनुरोध जांच और उसका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :
 - i सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है :-
 - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात की होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
 - (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
 - (3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।
 - ii गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय के रूप में विचार किया गया और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विविध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं, को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता है।

iii जहां तक इस तर्क का संबंध है कि लेन-देन वार आयात आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में सार्वजनिक फाइल में लेन-देन वार डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं।

ज. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन</u> उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अन्रोध

- 25. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अन्रोध किए गए हैं :
 - पूर्व के अंतिम समीक्षा जांच में, कुम्हो का पाटन मार्जिन केवल ***% था। वर्तमान जांच की जांच की अविध के दौरान, कुम्हो द्वारा कोई पाटन नहीं किया गया है।
 - ii. कुम्हों ने संबद्ध वस्तुओं का भारत में इसके कुल बिक्री का *** का निर्यात किया। यह आरोप कि कुम्हों ने भारत में अपने निर्यात के बारे में भ्रामक बयान दिए हैं, गलत है।
 - iii. कुम्हो एक बाजार अर्थव्यवस्था देश में कार्य कर रही है इस प्रकार इसने इसके घरेलू बाजार में मूल्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। कुम्हों ने उस सीमा तक जो संगत हो और उस तरीके से अधिसूचना प्रदान की है और उस रूप में यह सूचना दी है जो कोरिया के लेखांकन मानदंड के अन्रूप है।
 - iv. आवेदक द्वारा किया गया यह अनुरोध कि डी जी ए डी को उपभोग कारकों का सत्यापन करना चाहिए और उसकी तुलना आवेदक द्वारा रिर्पोट किए गए उपभोग के साथ करना चाहिए, का कोई अर्थ नहीं है। डी जी ए डी को कुम्हो द्वारा दी गई उपभोग मानदंडों के अनुसार ही कार्यवाही करनी चाहिए और यदि वह विश्वसनीय पाया जाये तो उसे स्वीकार करना चाहिए। उसकी तुलना आवेदक के उपभोग मानदंड के साथ करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
 - v. जांच की अविध के दौरान एल जी कैम लिमि. कोरिया जन. गण. ने मामूली मात्रा में निर्यात
 किया है और घरेलू उद्योग को इससे हानि नहीं हो सकती थी।
 - vi. याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का आकलन दोषपूर्ण और गैर कानूनी है। जबिक सामान्य मूल्य का निर्धारण याचिकाकर्ता के अपने कीमती के आधार पर, जो बाजार अर्थव्यवस्था देशों के मामले में कानून के अंतर्गत अधिकार प्राप्त नहीं है, किया गया है, निर्यात कीमत का निर्धारण अनुचित और सिद्ध न किए गए समायोजन द्वारा किया गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा लगातार पाटन का दावा करने के लिए तय किया गया पाटन मार्जिन दोषपूर्ण है।
 - vii घरेलू उद्योग 23 प्रतिशत के पाटन मार्जिन का दावा किया है। वह घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए बढ़े हुए सामान्य मूल्य के आधार पर है।
 - viii. पूर्व की जांच में प्राधिकारी ने माहवार विश्लेषण पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए कुम्हों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और बदले में प्राधिकारी ने जांच की अविध के लिए भारित औसत आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण किया। अत: प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह इस जांच में जांच की अविध की समग्र अविध के लिए भारित औसत आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करे।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- 26. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है :
 - ं. कुम्हों ने अनुरोध किया है कि उनके निर्यात में इस अविध के दौरान बमुश्किल 5-8 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी है। एल जी कैम ने उल्लेख किया कि भारतीय बाजार में उनका निर्यात मामूली था। इसके विपरीत आयात में 1992-93 में लगभग 419 मी. ट. से 2013-14 में 13,322

मी. ट. तक वृद्धि हुई है और कोरिया भारतीय बाजार में इस उत्पाद का बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कोरिया से आयात की मात्रा जो 1992-93 (मूल जांच का आधार वर्ष) में 400 मी. ट. के क्षेत्र में था, बहुत अधिक बढ़कर 14,000 मी. ट. हो गया है। ऐसा केवल इस कारण से हुआ है कि निर्यातकों द्वारा पाटन का सहारा लिया गया है।

- ii. प्राधिकारी को यदि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दिया जाये तब तृतीय देशों के संबंध में लेन-देन वार निर्यात आंकड़ों की जांच करनी चाहिए। अन्यथा प्रश्नावली के उत्तरों को अपूर्ण तथा अस्वीकार किया हुआ माना जाना चाहिए।
- iii. के पी सी ने असंबंधित कम्पनियों से कच्चा माल खरीदा। हालांकि, के पी सी ने बूटाडीन का भी उत्पादन किया है और इसका उपयोग संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए किया है। इस पहलू पर प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी को अवश्य ही इनपुट्स की इन-हाउस उपभोग की जटिलता जैसे कीमत अंतरण तथा संबंधित पक्षकार के लेन-देन पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए निर्यातक के आंकड़ों की जांच करनी चाहिए।
- iv. पूर्व की जांच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन, इनपुट्स की कीमतों, उत्पादन के कारकों और न्यूनतम लागत जिसका वहन उत्पादन करने में तथा उत्पाद की बिक्री करने में किसी उत्पादक द्वारा किया जाना चाहिए, पर विचार करते हुए बहुत कम है। उत्पादन की लागत जिसका निर्धारण किया जाना चाहिए और जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह लागत होनी चाहिए जो सामान्य लागत हो और न कि विशिष्ट लागत। ऐसी लागतों को सामानों के अंतरनिहित मूल्य को दर्शाना चाहिए।
- v. लागतों के कारकों यदि वह निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर हो, फिर भी यह नहीं बताता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर संतुष्ट हुए हैं कि निर्यातक के उत्पादन की लागत को अपनाने के लिए बाध्य है कि वह उचित रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को दर्शाता है। ऐसी लागतों को उचित रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को दर्शाना चाहिए।
- vi. वर्तमान उत्पाद में कोरिया की कम्पनियों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण बहुत बड़े विवाद का मसला बना हुआ है। घरेलू उद्योग हमेशा से यह तर्क देता रहा है कि निर्धारित पाटन मार्जिन विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत के उचित आकलन पर विचार करने के बाद बहुत कम है। निर्यातक द्वारा उपभोग किए गए केपटिव इनपुट को उनके बाजार मूल्य पर लिया जाना अपेक्षित है।
- vii संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। बहुत अधिक पाटन का होना घरेलू उद्योग को हानि पहुंचाने वाले सतत हानि के होने का स्पष्ट प्रमाण है।
- viii. संबद्ध देश से निर्यातक और उत्पादक ने पाटन रोधी शुल्क के लगाये जाने के बाद भी पाटित कीमतों पर सामग्री का निर्यात करना जारी रखा है। यह देखते हुए कि विगत में संबद्ध देश से लगातार पाटन होता रहा है। इस बात पर विचार करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान मामले में करों को समाप्त करने के फलस्वरूप इस स्रोत से बहुत अधिक पाटन होगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. पाटन विश्लेषण के तथ्य स्वतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया जन. गण. से प्रतिवादी सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना/ आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नान्सार किया गया है:

<u>सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

28. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्त् के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा
 - (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

बशर्ते यह कि उद्गम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जिरए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

- 29. एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन रबइ (एन बी आर) एक्रीलोनिट्राइल (ए सी एन) और बूटाडिन का एक सिंथेटिक रबड़ सह पोलीमर है। एन बी आर के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्चा माल एक्रीलोनिट्राइल और ब्टाडिन है। एन बी आर के विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा मृनी विस्कोसिटी और एक्रीलोनिट्राइल मात्रा के संबंध में दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के एन बी आर का उत्पादन और बिक्री घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में किया जाता है। यद्यपि, विभिन्न उपयोगों के लिए उपयुक्त मूनी विस्कोसिटी और एक्रीलोनिट्राइल मात्रा के आधार पर अनेक पी सी एन हैं परंत् एन बी आर में प्रमुख लागत बढ़ाने वाला कारक अंतिम उत्पाद में बूटाडिन और एक्रीलोनिट्राइल मोनोमर्स की संरचना है। ए सी एन की मात्राओं के आधार पर, इस उत्पाद को मोटे तौर पर 36 प्रतिशत - 45 प्रतिशत (अधिक) 31 प्रतिशत - 35 प्रतिशत (मध्यम) और 26-30 प्रतिशत (निम्न) ए सी एन की मात्रा वाले तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादन और घरेलू बिक्री में मध्यम ए सी एन श्रेणी का हिस्सा 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत है और जांच की अवधि के दौरान दोनों सहयोगी निर्यातकों से भारत में इस विशिष्ट श्रेणी का निर्यात लगभग 95 प्रतिशत था। इसके अलावा, इन श्रेणियों में से प्रत्येक में कच्चे माल की लागत की त्लना ने यह दर्शाया कि मध्यम ए सी एम श्रेणी से अंतर केवल 1 से 1.5 प्रतिशत था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं समझते हैं कि वह श्रेणीवार सामान्य मूल्य का निर्धारण करे। बदले में प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्रोध पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह उपयुक्त समझते हैं कि वह मासिक आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करे और तदन्सार निवल निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करे। डी जी ए डी में मौजूद प्रथाओं के अनुसार, 80/20 परीक्षण को लागू करने के बाद प्रत्येक माह की घरेलू इकाई बिक्री कीमत की त्लना उसी माह के लिए औसत इकाई लागत के साथ की गई और लाभ वाले लेन-देन की घरेलू एक्स फैक्ट्री कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में अपनाया गया है।
- 30. कोरिया जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

- i. क्म्हो पैट्रोकेमिकल कं. लिमि. (के पी सी)
- ii. एल जी केम लिमि. (एल जी)

कुम्हो पैट्रोकेमिकल के. लिमि. (के पी सी)

31. वर्तमान जांच में कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि., कोरिया जन. गण. (उत्पादक/ निर्यातक) ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया था। सत्यापन के दौरान यह सूचित किया गया था कि 14 मार्च, 2008 से कम्पनी का नाम कोरिया कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लिमि. से बदलकर कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि. कर दिया गया है। जांच की अविध के दौरान के पी सी ने के आर डब्ल्यू *** का कुल एक्स फैक्ट्री मूल्य के लिए घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं का *** मी. ट. बेचा। सभी घरेलू बिक्री के पी सी द्वारा असंबंधित पक्षकारों को किया गया था। प्राधिकारी ने लेन-देन का माहवार विश्लेषण किया था और जांच की सामान्य अविध के लिए आवेदन किया था। पैकिंग के खर्चे, अंतरदेशीय धारा और कर्ज संबंधी खर्च के मद में उचित समायोजन करने के बाद, प्राधिकारी ने के पी सी के लिए सामान्य मूल्य को *** अमरीकी डालर प्रति मी. ट. निर्धारित किया है।

एल जी केम लिमि (एल जी)

32. वर्तमान जांच में एल जी केम लिमि., कोरिया जन. गण. (उत्पादक/ निर्यातक) ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया था। सत्यापित सूचना/ आंकड़ों के आधार पर, जांच की अविध के दौरान, एल जी ने के आर डब्ल्यू *** और यू एस डालर *** के मूल्य का संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री का *** मी. ट. किया। संबद्ध वस्तुओं की कुल घरेलू बिक्री में से, लगभग 0.18 प्रतिशत बिक्री संबंधित पक्षकारों को किया गया था तथा शेष 99.82 प्रतिशत असंबंधित पक्षकारों को बेचा गया था। चूंकि, संबंधित पक्षकारों को की गई बिक्री का औसत बिक्री प्राप्ति अन्य असंबंधित पक्षकारों की तुलना में कम नहीं थी फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा, प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 1 में दी गई सूचना के अनुसार, कम्पनी ने एन बी आर पाउडर को भी शामिल किया था जो संबद्ध वस्तुओं का हिस्सा नहीं है और जिसे सामान्य मूल्य तय करने के उद्देश्य से अलग कर दिया गया है। अतः *** के आर डब्ल्यू (*** यू एस डालर समतुल्य) के एक्स फैक्ट्री मूल्य के साथ *** मी. ट. की घरेलू बिक्री हुई। प्राधिकारी ने लेन-देन का माहवार विश्लेषण किया था और जांच की सामान्य अविध के लिए आवेदन किया था। पैकिंग के खर्च, अंतरदेशीय धारा और कर्ज संबंधी खर्च के मद में उचित समायोजन करने के बाद, प्राधिकारी ने एलजी के लिए सामान्य मूल्य को *** यू एस डालर प्रति मी. ट. के रूप में निर्धारित किया है।

अन्य सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मुल्य का निर्धारण

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपर्युक्त निर्यातकों के अलावा कोरिया जन. गण. के किसी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। कोरिया जन. गण. में विचाराधीन उत्पाद के सभी गैर सहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य को *** यू एस डालर प्रति मी. ट. के रूप में निर्धारित किया है।

निर्यात मूल्य

कम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लिमि. (के पी सी)

34. जांच की अविध के दौरान के पी सी ने, *** यू एस डालर के मूल्य के लिए भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. का निर्यात किया था। भारत में विचाराधीन उत्पाद निर्यात का प्राय: *** प्रतिशत मध्यम श्रेणी का हुआ। पैकिंग खर्च, अंतरदेशीय और समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, पोर्ट पर खर्च, सीमा पर ब्रोकर का शुल्क, कर्ज संबंधी खर्च, बैंकों के शुल्क, और बिक्री का कमीशन के मद में उचित समायोजन करने के बाद प्राधिकारी ने जांच की अविध के दौरान *** यू एस डालर प्रति मी. ट. के रूप में के पी सी के निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

एल जी केम लिमि (एल जी)

35. जांच की अविध के दौरान एल जी ने, *** यू एस डालर के मूल्य के लिए भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मी. ट. का निर्यात किया था। भारत मे विचाराधीन उत्पाद निर्यात का प्राय: 95 प्रतिशत मध्यम श्रेणी का हुआ। इसमें अप्रत्यक्ष निर्यात की अल्प मात्रा भी शामिल थी जिसके लिए प्रश्नावली का उत्तर निर्यातक/ आयातक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: केवल *** मी. ट. के प्रत्यक्ष निर्यात पर निवल निर्यात कीमत की गणना के उद्देश्य से विचार किया गया है। पैकिंग खर्चे, अंतरदेशीय और समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, पोर्ट पर खर्च, सीमा पर ब्रोकर का शुल्क, कर्ज संबंधी खर्च, बैंकों के शुल्क, और बिक्री का कमीशन के मद में उचित समायोजन करने के बाद प्राधिकारी ने जांच की अविध के दौरान *** यू एस डालर प्रति मी. ट. के रूप में एल जी के निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

कोरिया जन. गण. के असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण

36. कोरिया जन. गण. से अन्य सभी निर्यातकों जिन्हें असहयोगी माना जाता है, के संबंध में, प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उनके निवल निर्यात कीमत का निर्धारण *** यू एस डालर प्रति मी. ट. के रूप में किया है।

झ. <u>पाटन मार्जिन</u>

37. ऊपर में निर्धारित किए गए अनुसार एक्स फैक्ट्री स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश में सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :-

		के पी सी	एल जी	अन्य
सामान्य मूल्य	अमरीकी डॉलर/ मी. ट.	***	***	***
निबल निर्यात मूल्य	अमरीकी डॉलर/ मी. ट.	***	***	***
पाटन मार्जिन	अमरीकी डॉलर/ मी. ट.	***	***	***
निवल निर्यात् कीमत (एन ई पी) का प्रतिशत के रूप में पाटन मार्जिन प्रतिशत	%	***	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज %	0-10%	0-10%	0-10%

ज. <u>हानि के निर्धारण के लिए पद्धति और हानि एवं कारणात्मक संबंध की जांच</u> <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

- 38. घरेलू उद्योग ने हानि और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अन्रोध किए हैं :
 - यह तथ्य कि भारत में उपभोग भारतीय उत्पादक के पास उपलब्ध क्षमताओं से अधिक है अपने आप में आयात को न्यायोचित ठहरा सकता है। हालांकि वह पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पाटन का सहारा लेने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का कोई तर्क/ अवसर नहीं है। देश में अनिवार्य आयातों को देखते हुए, घरेलू उद्योग प्रमुख विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की मूल्य पेशकश पर विचार करते हुए अपनी कीमतों को निर्धारित करने के लिए बाध्य है और अपनी लागत पर विचार न करने के लिए बाध्य है। चूंकि, विदेशी उत्पादक पाटन का सहारा ले रहे हैं अतः घरेलू उद्योग इस प्रकार की पाटित कीमतों का पालन करने के लिए मजबूर है।
 - मंबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पाटन रोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद पूरी जांच की अविधि में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान पाटन रोधी शुल्क संबद्ध देश से पाटित आयातों पर नियंत्रण पाने के लिए अपर्याप्त है।

- III. आयातों का अवतरित मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है। आयातों से इस बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। संबद्ध देश से आयातों का अवतरित मूल्य भी घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और एन आई पी की त्लना में बहत कम है।
- IV. आयातों का अवतिरत मूल्य जांच की पूरी अविध के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से बहुत कम है जो मूल्य में गितरोध की ओर संकेत देता है। आयात का बहुत अधिक गितरोधी प्रभाव बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भी है। प्रभाव ऐसा है कि घरेलू उद्योग बिक्री की लागत में वृद्धि के अनुपात में अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं था, जिससे भारी वित्तीय घाटा हो रहा है।
- V. जबिक, उत्पादन की लागत और बिक्री मूल्य 2011-12 में और उसके बाद 2012-13 में बढ़ा है तथापि, बिक्री मूल्य में 2012-13 में गिरावट आई जब उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। जांच की अविध में भी, उत्पादन की लागत में कुछ हद तक गिरावट आई, 2012-13 में और जांच की अविध में बिक्री के मूल्य में यह गिरावट उत्पादन की लागत में गिरावट की तुलना में अभी भी बहुत अधिक है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव प्रतिकृत और बहुत अधिक रहा है।
- VI. याचिकाकर्ता का उत्पादन और क्षमता के उपयोग में भी इस पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री में भी इस पूरी अवधि के दौरान गिरावट आई। घरेलू उद्योग की प्रतिकूल स्थिति (क) पाटन रोधी शुल्क के मौजूद रहने (ख) घरेलू उद्योग के पास क्षमताओं से बहुत अधिक उत्पाद की मांग के बावजूद हुई है। यह दर्शाता है कि लगाया गया पाटन रोधी शुल्क पर्याप्त नहीं है।
- VII. घरेलू उद्योग 2011-12 में कुछ लाभ अर्जित कर सका और तब बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई। लाभप्रदता में गिरावट के फलस्वरूप, घरेलू उद्योग नकद घाटा हुआ है और निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है।
- VIII. घरेलू उद्योग के औसत माल स्तर में भी गिरावट आई है। यह इस कारण से हुआ है कि घरेलू उद्योग माल भंडार को नियंत्रित करता रहा है और वित्तीय की मात्रा पर विचार करते हुए उत्पादन किया जा रहा है।
- रोजगार के स्तर में जांच की अविध के दौरान गिरावट आई है, हालांकि मजदूरी में वृद्धि हुई
 है।
- X. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में जांच की अविध के दौरान उत्पादन में गिरावट के अनुसार गिरावट आई है। यदि उत्पाद पर पाटन रोधी शुल्क हटा दिया जाए तब घरेलू उद्योग की उत्पादकता को और अधिक नुकसान होगा।
- XI. संबद्ध देश और अन्य देशों से आयात की कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रितस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर वे कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, पर विचार करना दर्शाता है कि संबंध देश से आयातित माल का अवतिरत मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में बहुत अधिक कीमत में कटौती हो रही है और अन्य देशों से संबंध वस्तुओं का आयात बहुत ऊंची कीमत पर है।
- XII. संबध वस्तुओं की मांग पर्याप्त वृद्धि को दर्शा रही थी और यह वह कारक नहीं हो सकता था जिससे घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इस प्रकार से घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक संबध देश से संबध वस्तुओं का अवतरित मूल्य है और घरेलू उदयोग के उत्पादन की लागत है।

- XIII. भारत में उत्पाद की मांग में सकारात्मक और बहुत वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की क्षमता मांग की तुलना में कम है, इसके बावजूद कि घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा भारतीय बाजार में पाटित आयातों की मौजदूगी के कारण गिरावट आई। दूसरी ओर, संबंध देश से पाटित आयातों की मात्रा जांच की अविध के दौरान बहुत अधिक बढ़ गई है।
- XIV. बिक्री, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बाजार का हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही थी। यह स्पष्ट रूप से बाजार में विचाराधीन उत्पाद के सतत पाटन के कारण हुई है।
- XV. लगातार कोरिया द्वारा पाटन किए जाने के कारण उत्पाद का सतत प्रतिकूल कार्य निष्पादन ने घरेलू उद्योग को क्षमता के विस्तार के संबंध में आगे बढ़ने से रोक दिया है।
- XVI. घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण लगातार हानि उठानी पड़ रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को निवेश पर उचित दर से लाभ अर्जित करना अभी बाकी है। सर्वप्रथम घरेलू उद्योग इस देश में बहुत अधिक और पर्याप्त मांग होने के बावजूद अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं है।
- XVII. संबंध देश से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कीमत में बहुत अधिक कटौती करनी पड़ रही है। यदि वर्तमान पाटन रोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है तब स्पष्ट संभावना इस बात की है कि कीमत में कटौती आगे और अधिक होगी।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

- 39. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित हानि से संबंधित अनुरोध किए गए हैं :
 - संबध वस्तुओं के आयातों की कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कोई संबंध नहीं है।
 - घरेलू उद्योग की क्षमता भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
 - iii. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए ह्रास की प्रवृत्ति और स्थिर परिसंपत्तियों के प्रवृत्ति में एक बहुत बड़ी विसंगति है। जबिक याचिकाकर्ता की स्थिर परिसंपत्ति जांच की पूरी अविध के दौरान लगातार कम हुई है, ह्रास लगातार बढ़ा है।
 - iv. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय का घरेलू उद्योग का दावा अनुचित और निराधार है।
 - v. आवेदक का विश्लेषण कि आयातों में उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, के विपरीत यह एक अन्य मार्ग है क्योंकि यह उत्पादन है जो कम अथवा ज्यादा स्थिर रहते हुए आयात में वृद्धि के साथ बहुत अधिक कम हो गया है। यदि यह संबद्ध आयातों में वृद्धि मात्र होता तब उसमें कुल आयात की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि भी हुई होती।
 - vi. आवेदक ने आकलन योग्य मूल्य के बजाय सी आई एफ मूल्य में मूल सीमा शुल्क और सीमा उप-कर को जोड़कर गलत ढंग से अवतरित मूल्य की गणना की है। इसने अवतरित मूल्य को कम दर्शाया है और समग्र कीमत प्रभाव को गलत कर दिया है।
 - vii दो मध्याविध समीक्षाएं और दो अंतिम समीक्षाएं पहले ही की जा चुकी हैं जिनमें पाटन मार्जिन हानि के मार्जिन से कम था। इसका अर्थ यह होता है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन के अलावा अन्य कारण भी थे, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि हुई।
 - viii. पाटन और हानि के मार्जिन का निर्धारण मासिक आधार पर प्रमुख कच्चे मालों की कीमतों में व्यापक अंतर के कारण एन बी आर की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव के कारण किया जाना चाहिए।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

- 40. प्राधिकारी द्वारा इसके नीचे किए गए हानि का विश्लेषण अपने आप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा संगत माने गए विशिष्ट अन्रोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए अन्सार किया गया है:
 - i. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग की क्षमता भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को देश की समग्र मांग को पूरा करने के लिए अधिकार देने के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
 - ii. इस अनुरोध के संबंध में िक डी जी ए डी द्वारा अनुमित दी गई नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय उचित नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं िक नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की स्वीकृति देना डी जी ए डी में एक सतत प्रथा है।
 - iii. इस तर्क के संबंध में कि जबकि याचिकाकर्ता की स्थिर परिसंपत्तियों में जांच की पूरी अविध के दौरान गिरावट आई है, हास सतत रूप से बढ़ा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की हानि रहित कीमत का निर्धारण पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध III के संबंध में किया गया है।
 - iv. इस अनुरोध के संबंध में कि जांच की अविध के लिए पाटन और हानि का मार्जिन का निर्धारण मासिक आधार पर प्रमुख कच्चे मालों की कीमतों में व्यापक अंतर के कारण एन बी आर की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव के कारण किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन का मार्जिन और हानि के मार्जिन का निर्धारण मासिक आधार पर किया गया है।
- 41. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी संबद्ध देश से आयात के कारण पाटन और हानि के पहलुओं की संभावना की जांच करने के लिए कार्यवाही के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान हानि, यदि कोई हो, की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।
- 42. अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षिति जांच में ".... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सिहत सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए...'' ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षित का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्यापाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
- 43. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की हालत पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
- 44. वर्तमान जांच लागू पाटन रोधी शुल्कों की एक अंतिम समीक्षा है। नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान किसी समीक्षा की स्थित में भी आवश्यक परिवर्तनों सिंहत लागू होंगे। इस कारण से प्राधिकारी ने अनुबंध II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर आवश्यक परिवर्तनों सिंहत विचार करते हुए घरेलू उद्योग की हानि का निर्धारण किया है। इसके अलावा, चूंकि पाटन रोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू हैं। अतः प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि क्या कोरिया जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटन रोधी शुल्क पर घरेलू उद्योग को हानि की जांच करते समय विचार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने इस बात की भी जांच की है कि क्या मौजूदा पाटन रोधी उपाय पाटन जिससे हानि हो रही है, का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं।

- 45. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि उसे पहले समाप्त नहीं किया गया हो, इसके लगाये जाने की तारीख से 5 वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जायेगा बतर्शे की यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से संभवत: पाटन और हानि के जारी रहेगा अथवा वह बार-बार होगा, यह समय समय पर 5 वर्षों की एक अतिरिक्त अविध के लिए इस शुल्क को लगाने की अविध में विस्तार कर सकता है और आगे की यह अविध इसके विस्तार के आदेश की तिथि से शुरू होगी।
- 46. वर्तमान जांच के विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों का मूल्य और मात्रा के प्रभावों और पाटन तथा हानि के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो तथा हानि की मौजूदगी की जांच करने के लिए मूल्य और लाभप्रदत्ता पर इसके प्रभावों की जांच की है। प्राधिकारी ने मैसर्स ओमनोवा सोल्यूशन (इंडिया) प्रा. लिमि. जो नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग है, के संबंध में सूचना पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को होने वाली हानि की जांच की है। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य पर प्रभाव की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

मात्रा का प्रभाव

पाटित आयातों की मात्रा का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग और बाजार का हिस्सा

47. प्रिधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के लिए संबद्ध देश से सहयोगी निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयात मात्रा और मूल्य डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों में इसके बारे में दी गई सूचना की तुलना में *** मी. ट. अधिक है। इसको देखते हुए प्रिधिकारी ने जांच की अविध के लिए सहयोगी निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य को स्वीकार कर लिया है। प्रिधिकारी ने इस देश में उत्पाद की मांग और स्पष्ट उपभोग का निर्धारण सभी म्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्री के योग के रूप में की है। इस प्रकार से आंकलित मांग को नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है। प्रिधिकारी नोट करते हैं कि इस देश में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में जांच की अविध सिहत हानि की पूरी अविध के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। उसके अलावा संबद्ध देश से आयात में जबिक घरेलू मांग के अनुरूप वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है। प्रिधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का बाजार का हिस्सा जांच की अविध के दौरान कम हुआ है जबिक संबद्ध देश का बाजार हिस्सा तथा अन्य देशों से आयात में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान वृद्धि हुई है।

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
मांग	मी. ट.	24,300	25,751	31,961	33,691
प्रवृत्ति	%	100	106	132	139
आयात - कोरिया जन.					
गण.	मी. ट.	7,596	7,808	11,187	13,585
आयात - अन्य देश	मी. ट.	8,657	10,605	14,493	14,079
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	8407	7338	6281	6027
मार्किट शेयर					
संबद्ध आयात	%	31	30	35	40
अन्य आयात	%	36	41	45	42
घरेलू उद्योग	%	33	29	20	18

48. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या उपभोग की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
कोरिया जन गण	मी. ट.	7,596	7,808	11,187	13,585
अन्य देश	मी. ट.	8,657	10,605	14,493	14,079
कुल आयात	मी. ट.	16,253	18,413	25,680	27,664
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध	देश से आयात				
कुल आयात	%	47	42	44	49
भारत में उपभोग	%	29	29	34	39
भारत में उत्पादन	%	80	91	153	191

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा घरेलू मांग और उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयात में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

मूल्य का प्रभाव

पाटित आयातों का मूल्य का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

50. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यों पर प्रभाव की जांच मूल्य में कटौती, कम मूल्य पर बिक्री, मूल्य पर दबाव और मूल्य के रुकावट के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री की प्राप्ति (एन एस आर) और अहानिकर मूल्य (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से आयात के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। जांच की अविध के दौरान संबद्ध वस्तुओं की एक तुलना पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री मूल्य के बीच की गई थी। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में करों, छूट, बट्टे और कमीशन जिसका भुगतान घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है, का समायोजन किया गया है। कम मूल्य पर बिक्री हानि के आकलन का एक प्रमुख सांकेतक है और इस प्रकार प्राधिकारी ने अहानिकर मूल्य तय किया है और उसकी तुलना कम मूल्य पर बिक्री की सीमा तय करने के लिए लैंडिड मूल्य के साथ की गई है। अहानिकर मूल्य का मूल्यांकन घरेलू उद्योग के लिए जांच की अविध के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत पर उपयुक्त रूप से विचार करते हुए नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के मामले में घरेलू उद्योग के लिए किया गया है। स्थिति नीचे दी गई है:

मूल्य कटौती एवं कम मूल्य पर बेचना

51. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार पाटन रोधी शुल्क के साथ और उसके बिना मूल्य कटौती एवं कम मूल्य पर बिक्री दोनों का विश्लेषण किया है :

<u>मूल्य में कटौती</u>

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
विक्रय मूल्य	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	123	111

 लैंडिड मूल्य – कोरिया जन गण	रु/ मी. ट.	1,38,151	1,82,931	1,79,736	1,49,123
मूल्य में कटौती	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
मूल्य में कटौती %	%	***	***	***	***
मूल्य में कटौती %	रेंज	10-20%	10-20%	5-15%	10-20%
पाटन मार्जिन शुल्क के साथ					
लैंडिड मूल्य – कोरिया जन गण	रु/ मी. ट.	1,39,999	1,84,986	1,81,704	1,51,289
मूल्य में कटौती	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
मूल्य में कटौती %	%	***	***	***	***
मूल्य में कटौती %	रेंज	10-20%	10-20%	5-15%	5-15%

कम मूल्य पर बेचना

विवरण	यूनिट	यू ओ आई
घरेलू उद्योग हानि रहित मूल्य	रु/ कि. ग्रा.	***
लैंडिड मूल्य	रु/ कि. ग्रा.	1,49,123
कम लागत पर बेचना	रु/ कि. ग्रा.	***
	%	***
	रेंज %	10-20

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों का लैंडिड मूल्य पाटन रोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य से कम है जिसके फलस्वरूप मूल्य में बहुत अधिक कटौती होती है। इसके अलावा कम मूल्य पर बिक्री का प्रभाव भी बहुत अधिक है।

मूल्य पर दबाव एवं रुकावट

53. घरेलू मूल्य पर पाटित आयातों के मूल्य पर दबाव और रुकावट संबंधी प्रभावों की जांच करने के लिए, घरेलू उद्योग का निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति की तुलना बिक्री की लागत से की गई है। नीचे दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत 2011-12 को छोड़कर जांच की पूरी अविध के दौरान बिक्री की इसकी लागत से कम रही है, जो मूल्य पर दबाव के प्रभाव होने को दर्शाता है।

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
बिक्री की लागत मूल्य	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	126	134	115
निवल बिक्री मूल्य	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	136	123	111

ट. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानदण्डों की जांच

54. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि हानि के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस

नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित वस्तुओं के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन तथा बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार का हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग, घरेलू मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन के आकार में वास्तविक और संभावित गिरावट, नकदी के प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश प्राप्त करने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों वाले सूचकांक शामिल किए जाने चाहिए। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच यह उजागर करती है कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त हानि हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न हानि मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

बिक्री, उत्पादन, क्षमता का उपयोग

55. प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका से नोट करते हैं घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता का उपयोग देश में मांग में वृद्धि और पाटन रोधी उपायों के लगातार लगाए जाने के बावजूद हानि की अविध के दौरान कम हुई।

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
क्षमता	मी. ट.	11,000	11,000	11,000	11,000
उत्पादन	मी. ट.	10,349	9,196	7,874	7,390
क्षमता का उपयोग	%	94	84	72	67
घरेलू बिक्री	मी. ट.	8,047	7,338	6,281	6,027
मांग	मी. ट.	24,300	25,751	31,961	33,691

लाभ/ घाटा, निवेश पर आय और नकदी का प्रवाह

56. निवेश पर आय, ब्याज पूर्व और ब्याज बाद लाभ/ हानि तथा नकद लाभ नीचे तालिका में दर्शाये गए हैं :

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
बिक्री की लागत	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	134	115
बिक्री मूल्य	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	136	123	111
लाभ/ घाटा	रु/ मी. ट.	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	28	(264)	(144)
लाभ/ घाटा	रु. लाख	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	25	(201)	(103)
ब्याज एवं कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22583	(17507)	(8242)
नकद लाभ	रु. लाख	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	78	(210)	(82)
निवेश पर आय	%	***	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	884	(957)	(430)

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री की लागत में 2012-13 तक वृद्धि हुई है और तब जांच की अविध में यह कम हुई है। बिक्री का मूल्य 2011-12 में बढ़ा है और तब 2012-13 और जांच की अविध में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग 2011-12 में कुछ लाभ अर्जित कर सका और तब बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई। लाभप्रदता में गिरावट के फलस्वरूप, घरेलू उद्योग नकद घाटा हुआ है और निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है।

<u>माल भंडार</u>

58. नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गये आंकड़े बताते हैं कि घरेलू उद्योग का संबद्ध वस्तुओं के माल भंडार में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान गिरावट आई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में मांग आपूर्ति से अधिक है तथापि माल भंडार अधिक रहा है।

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
औसत माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	84	77

रोजगार एवं मजदूरी

59. नीचे दी गई तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अविध के दौरान गिरावट आई है। तथापि यह नोट किया जाता है कि मजूदरी में वृद्धि हुई है।

अवधि	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	100	95	90
मजदूरी	रु लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	128	162	163

<u>उत्पादकता</u>

60. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता आधार वर्ष की तुलना में कम हुई है।

उत्पादकता	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
प्रति कर्मचारी	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	%	100	89	80	79
प्रति दिन	मी. ट.	29.57	26.27	22.50	21.11
प्रवृत्ति	%	100	89	76	71

मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक

61. संबद्ध देश और अन्य देशों से आयात की कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर वे कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं आदि की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित माल का पंहुच मूल्य पाटनरोधी शुल्क सिहत और उसके बिना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और हानि रिहत मूल्य से कम है जिससे भारतीय बाजार में पाटन रोधी शुल्क सिहत और उसके बिना मूल्य में बहुत अधिक कमी हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग जांच की अविध के दौरान बहुत अधिक वृद्धि को दर्शा रही है और इस कारण से यह वह कारक नहीं हो सकता था जो घरेलू मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। इस प्रकार, घरेलू मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। इस प्रकार, घरेलू मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वाले प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबंध वस्तुओं का पंह्च मूल्य है।

ठ. <u>पाटन मार्जिन का आकार</u>

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

ड. <u>विकास</u>

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने कुछ आर्थिक मानदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, मांग में बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आय आदि में नकारात्मक वृद्धि जांच की पूरी अविध के दौरान दर्शायी है।

विकास % (वर्ष दर वर्ष)	यू ओ एम	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
उत्पादन मात्रा	%	-	(11.14)	(14.38)	(6.15)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	(8.82)	(18.98)	(3.61)
बिक्री की लागत	%	-	25.08	6.46	(13.93)
बिक्री मूल्य	%	-	36.10	(9.38)	(9.95)
लाभ/ हानि	%	-	125	(896)	49
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	-	14	(26)	6

पुंजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का सतत पाटन जिससे लगातार पर्याप्त हानि हो रही है, को देखते हुए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग नए निवेश पर विचार नहीं कर सकता है।

ढ. <u>कारणात्मक संबंध</u>

- 65. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को हानि हो सकती थी जो निम्नानुसार है :
 - तीसरे देशों से आयात : प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का औसत मूल्य जांच की अविध के दौरान संबद्ध देश के आयातों के मूल्य से अधिक है और इस कारण से घरेलू उद्योग को हानि नहीं हो सकती थी।
 - मांग में कमी: प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि इस देश में संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की पूरी अविध के दौरान सतत रूप से वृद्धि हुई है।
 - खपत का पैटर्न : यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के खपत के पैटर्न में कोई बड़ा परिवर्तन प्राधिकारी के ध्यान में नहीं आया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है।

- ए. प्रतिस्पर्धा की स्थिति : प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं घरेलू उद्योग को दावा की गई हानि के लिए जिम्मेदार हैं।
- v. प्रौधोगिकी का विकास : प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रौद्योगिकी में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को हानि को सकती थी।
- VI. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन : घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि घरेलू उद्योग का मूल्य और लाभप्रदता को प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को हानि का आकलन करने के प्रयोजन से घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए अलग अलग रखा गया है।

ण. पाटन और हानि की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

- 66. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अन्रोध किए गए हैं :
 - संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का सतत पाटन हुआ है और इसके परिणामस्वरूप पाटन रोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद घरेलू उद्योग को लगातार हानि हुई है। संबद्ध देश से आयातों के विरुद्ध पाटन रोधी शुल्क (ए डी डी) को लगाए जाने के बावजूद, घरेलू उद्योग को लगातार भारतीय बाजार पाटित आयातों की लगातार मौजूदगी के कारण हानि उठानी पड़ती है। इससे स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को हानि की संभावना की जटिलता उत्पन्न होती है।
 - शा. लागू वर्तमान पाटन रोधी शुल्क बहुत कम है। संबद्ध देश से आयात की कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री मूल्य की तुलना में बहुत कम रही है क्योंकि निर्यातकों ने कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि की तुलना में अपने मूल्य में बहुत कम वृद्धि की। जहां कच्चे माल की कीमतों ने गिरावट दर्ज की, उसे निर्यात मूल्य में दर्शाया गया था। इस प्रकार से लगाए गए उपायों की मात्रा घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करने में असफल रहा है।
 - मंबद्ध देश से आयात की मात्रा में वास्तव में वृद्धि हुई है जब उसकी तुलना मूल जांच की हानि की अविध से की गई। पाटन रोधी शुल्कों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उचित बाजार स्थितियों के संबंध में पाटन को समाप्त करना और उस स्थिति को वापस करना है। यिद इस उत्पाद का लगातार पाटन नहीं हुआ होता तब आयात में गिरावट नहीं होती। वास्तव में, पाटित आयात का अधिक मात्रा में लगातार मौजूद रहने का कारण देश में इस उत्पाद का लगातार पाटन और न कि स्वस्थ व्यापार प्रथाएं हैं। जबिक घरेलू उद्योग पाटन के दुष्प्रभावों से निकलने की कोशिश कर रहा है फिर भी इसे इस देश में उत्पाद की लगातार पाटन को देखते हुए हानि उठानी पड़ रही है।
 - IV. वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन पूर्व की जांच की तुलना में अधिक है और जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन होने की संभावना है और इसके फलस्वरूप हानि होगी। यह स्पष्ट रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि पाटन जारी रहने की संभावना है और वास्तव में वर्तमान पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में यह और अधिक होगा।
 - v. संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्सा मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों के बावजूद बहुत अधिक है।

- VI. संबद्ध देश में उत्पादक घरेलू मांग से बहुत अधिक एन बी आर का उत्पादन करने के लिए विशाल क्षमताएं बनाए रखते हैं। वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देश से पाटन निश्चित रूप से जारी रहेगा और वास्तव में यह और अधिक होगा और अंततः इससे बहुत अधिक मात्रा और मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग को हानि होगी।
- VII. भारतीय बाजार बहुत अधिक मूल्य संवदेनशील है। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, घरेलू उद्योग को और अधिक मूल्य में कमी लानी पड़ेगी अथवा बहुत अधिक बिक्री मात्राओं को खोना पड़ेगा। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात मूल्य पर बेचने का विकल्प अपनाता है तब घरेलू उद्योग को लाभप्रदता के मामले में और अधिक हानि उठानी पड़ेगी।
- VIII. संबद्ध देश से आयात में बहुत अधिक कटौती हो रही है और यदि वर्तमान पाटन रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तब घरेलू उद्योग को कीमतों में कटौती करना जारी रखना पड़ेगा। भारतीय कीमतें विदेशी उत्पादकों के लिए बहुत आकर्षक हैं और यह आयात में और आगे वृद्धि लायेगा।
- IX. यह आवश्यक नहीं है कि सभी स्थितियां शुल्क को जारी रखने के लिए मौजूद रहनी चाहिए। यदि एक अथवा उससे अधिक मानदंडों को पूरा कर लिया जाता है तब पाटन रोधी शुल्क को जारी रखा जा सकता है।
- X. संबद्ध देश में उत्तर देने वाले निर्यातकों को निश्चित रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन के के जारी रहने की संभावना नहीं है। यदि निर्यातक सूचना के आधार पर सिद्ध करते हैं कि पाटन जारी रहने की संभावना नहीं है अथवा पाटन रोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में यह और अधिक नहीं होगी तब निर्दिष्ट प्राधिकारी को निश्चित रूप से यह मानना चाहिए कि पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन जारी रहेगा और यह और अधिक होगा, जिससे घरेलू उद्योग को हानि होगी।
- XI. कारणात्मक संबंध पूर्व की सभी जांचों में पहले ही सिद्ध की जा चुकी है। वर्तमान अंतिम समीक्षा जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी है कि क्या पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और हानि के जारी रहने अथवा उसके बार बार होने की संभावना है। हालांकि, पाटन और उसके परिणामस्वरूप हानि की संभावना के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- XII. घरेलू उद्योग को वर्तमान हानि भारत में पाटित आयातों के कारण होती है। इसे स्पष्ट रूप से पर्याप्त मूल्य कटौती, कम मूल्य पर बिक्री, मूल्य पर दबाव/ गितरोध, स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं उपभोग की तुलना में आयात की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, बिक्री, बाजार का हिस्सा, लाभ, नकदी का प्रवाह और निवेश पर आय से सिद्ध हो गया है। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट देश में पाटित आयातों के कारण हुआ है।

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

- 67. परस्पर प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए है :
 - (i) कुम्हो आदर्शतम से अधिक क्षमता उपयोग पर पहले से ही कार्य कर रहा है। फलस्वरूप यदि कोई वैध शुल्क अधिसूचना रद्द की जायेगी तब इसको भारत में संबद्ध वस्तुओं के अपने उत्पादन को परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं होगी।
 - (ii) यह अनुरोध कि कोरिया में पर्याप्त रूप से तथा स्वतंत्र रूप से बेचने योग्य क्षमता मौजूद है, पूर्ण रूप से सही नहीं है।

- (iii) कुम्हो अन्य देशों में अपने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री उन कीमतों पर पहले से कर रहा है जो भारत में निर्यात कीमतों की तुलना में बहुत अधिक है। इसके फलस्वरूप पहले से अपेक्षाकृत अधिक कीमतों के साथ, शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप भारत में अन्य देशों से निर्यात परिवर्तित नहीं होंगे। इस प्रकार कुम्हो द्वारा संबद्ध वस्तुओं के पाटन की कोई संभावना नहीं है।
- (iv) कुम्हों ने पूर्व जांच की हानि अविध के प्रारंभ से अपनी क्षमताओं को नहीं बढ़ाया है। इस प्रकार से जहां तक कुम्हों का प्रश्न है, क्षमताओं को बढ़ाने के आरोप में कोई दम नहीं है। इसके अलावा पूर्व जांच में कुम्हों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण केवल 1.69 प्रतिशत किया गया था। वर्तमान जांच में पाटन का मार्जिन कुम्हों के लिए नकारात्मक है। इसके फलस्वरूप सतत पाटन का आरोप भी सही नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

68. वर्तमान जांच कोरिया जन. गण. से संबद्घ वस्त्ओं के आयातों पर लगाये गये पाटनरोधी श्ल्कों की अंतिम समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात का निर्धारण करे कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखना आवश्यक है। इससे इस बात की भी जांच की अपेक्षा है कि क्या लगाये गये श्ल्क से हानिकर पाटन को समाप्त करने के निहित उद्देश्य सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान जांच में, चूंकि घरेलू उद्योग को लगातार हानि पहुंचाते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्त्ओं का सतत पाटन हुआ है, जो अपने आप में पाटन और हानि की संभावना को दर्शाता है। प्राधिकारी से इस बात की जांच करने की अपेक्षा नहीं है कि क्या श्लक को हटाये जाने से घरेलू उद्योग को हानि और सतत पाटन होगा। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते ह्ए कि पिछले और वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और यह कि जहां तक संबद्घ वस्त्ओं की मांग और मूल्य का संबंध है, भारतीय बाजार में अनुकूल बाजार परिस्थितियां हैं। प्राधिकारी के पास इस बात पर विश्वास करने का कारण है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो पाटन और अधिक हो सकता है। यह सच है कि लागू पाटनरोधी उपायों के बावजूद संबद्ध देश ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन करना जारी रखा है। निम्नलिखित विश्लेषण पाटनरोधी श्ल्क के हटाये जाने की स्थिति पाटन के जारी रहने/ उसके और अधिक होने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को नुकसान की संभावना को दर्शायेगा।

(i) <u>वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर</u>

69. मौलिक तथा वर्तमान जांच दोनों में पाटन के मार्जिन का स्तर सकारात्मक है। कोरिया जन. गण. में क्षमता और भारत में मांग पर विचार करते हुए तथा मूल्य में कटौती कम मूल्य में बिक्री के स्तर को देखते हुए पाटन रोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयात की मात्रा आगे और अधिक होने की संभावना है।

(ii) <u>भारतीय बाजार के मूल्य का आकर्षण</u>

70. वह मूल्य जिस पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कोरिया जन. गण. द्वारा भारत को किया जा रहा है वह पाटन के लगातार होने/और अधिक होने की संभावना का एक संकेत है। भारत में वर्तमान लैंडिड मूल्य पर पाटन रोधी शुल्क के होने पर भी मूल्य में सकारात्मक कटौती हुई है। इस प्रकार से पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और अधिक होने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को और अधिक हानि हो सकती है।

(iii) <u>कोरिया के उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण</u>

71. उपलब्ध सूचना से यह स्पष्ट है कि कोरिया के उत्पादक/निर्यातक बहुत अधिक निर्यात उन्मुख हैं। उच्च मांग और भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए बाजार की अनुकूल स्थितियों तथा जांच की अविध सिहत हानि की अविध के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में सतत वृद्धि पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि यदि मौजूदा पाटन रोधी शुल्क हटा दिया जाता है तब भारत में संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग को आसानी से कोरिया के निर्यातकों द्वारा पूरा किया जा सकता है।

त. हानि का आकार और हानि का मार्जिन

72. इस प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।।। के संबंध में यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के अहानिकर मूल्य की तुलना जांच की अविध के दौरान हानि के मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से सहयोगी निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात के लैंडिड मूल्य से तुलना की गई है और इस प्रकार से तय की गई हानि का मार्जिन नीचे दिया गया है:

विवरण	यू ओ एम	पी ओ आई		
		के पी सी	एल जी	अन्य सभी
हानि रहित मूल्य (मासिक एन आई पी का भारित औसत)	रु./ मी. ट.	***	***	***
बिना पाटन रोधी शुल्क के लैंडिड मूल्य	रु./ मी. ट.	***	***	***
हानि का मार्जिन	रु./ मी. ट.	***	***	***
	अमरीकी डालर/ मी. ट.	***	***	***
	%	***	***	***
	रेंज %	10-20	10-20	10-20

थ. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

- 73. प्रधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को लगाने से भारत में इस उत्पाद के मूल्य स्तरों पर प्रितंकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को पाटन रोधी से कम नहीं किया जायेगा। इसके विपरीत पाटन रोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जायेगा, घरेलू उद्योग को हानि होने से रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखा जा सकेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी उपायों के लगाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयात में रुकावट नहीं होगी और इस कारण से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता अब भी दो अथवा उससे अधिक आपूर्ति के स्रोत बनाए रख सकते हैं।
- 74. सामान्य तौर पर पाटन रोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई हानि को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है।

द. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

75. परस्पर विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए तथा इस प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई अन्रोध/टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :

- इस प्राधिकारी द्वारा प्रकटन टिप्पणियां प्रस्त्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
- II. वर्तमान जांच मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों के समाप्त होने के बाद अनुचित रूप से तथा गैर कान्नी रूप से शुरू किया गया था और इसे प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था।
- III. कुम्हो का विचार जाने बिना मासिक आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।
- IV. शुल्क वापसी समायोजन की अनुमित इस प्राधिकारी द्वारा निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित त्लना करने के लिए दी गई है।
- V. सामान्य मूल्य की गणना करते समय, प्राधिकारी को व्यापार समायोजन के स्तर की अनुमित देनी चाहिए थी। इससे यह प्राधिकारी निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच उचित प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होता है।
- VI. एक वर्ष से आगे अंतिम समीक्षा को जारी रखना गैर कानूनी है और इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। पाटन रोधी नियमावली का नियम 23 (2) विशिष्ट रूप से यह अधिकार देता है कि समीक्षा को ऐसी समीक्षा के शुरू होने की तिथि से अधिकतम 12 महीने की अविध के भीतर समाप्त की जायेगी।
- VII. घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और आयात के अवतिरत मूल्य में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि और आयात के अवतिरत मूल्य के बीच कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी इस पहलू की जांच नहीं कर सके हैं।
- VIII. घरेलू उद्योग के पास क्षमता भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी ने इस पहलू की भी उचित ढंग से जांच नहीं की है।
- IX. हानि रहित मूल्य की गणना करते समय घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमति देना उचित नहीं है।
- X. प्राधिकारी ने ह्रास लागत और स्थिर पड़ी सम्पित्तयों की जांच सही ढंग से नहीं की है। स्थिर परिस्थितियों में गिरावट के बावजूद ह्रास की लागत में लगातार और पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- XI. प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि इसने वर्तमान जांच में डी जी सी आई एंड एस द्वारा दिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। परंतु प्राधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि इसने जांच की अविध के लिए सहयोगी निर्यातकों द्वारा सूचित किए गए आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार किया है। हालांकि, पिछले वर्षों के लिए आयात के आंकड़ों का स्रोत ज्ञात नहीं है। इसको देखते हुए डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात के आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों को दिया जाना चाहिए।
- XII. जांच की अवधि के दौरान रूस के पास भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयात का न्यूनतम स्तर से अधिक था और वह कोरिया के आयात मूल्य की तुलना में कम था। प्राधिकारी को इस पहलू की जांच करनी चाहिए ताकि रूस से आयात को अस्वीकार किया जा सके और यह भी कि अन्य देशों से आयात से घरेलू उद्योग को हानि नहीं हुई है।
- XIII. सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई डी जी सी आई एंड एस का लेन-देन वार आयात आंकड़ा दर्शाता है कि इसमें अनेक विचाराधीन गैर उत्पाद शामिल हैं, जिसे भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का निर्धारण करते समय छोड़ दिया जाना चाहिए।
- XIV. घरेलू उद्योग के लाभ और घाटे तथा मूल्य में कटौती के रेंज के बीच कोई संबंध नहीं है। 2011-12 के दौरान जब घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया, तब मूल्य में बह्त अधिक

- कटौती हुई थी। हालांकि, बाद के वर्षों के दौरान जब घरेलू उद्योग को घाटा हुआ था, तब मूल्य में कटौती कम हुई थी।
- XV. प्राधिकारी इस बात की भी जांच करने में असफल रहा है कि जबकि घरेलू उद्योग के रोजगार का स्तर हानि की अविध के दौरान कम हुआ है, इसकी मजदूरी में सतत रूप से और पर्याप्त रूप से उस अविध के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के परिणामी प्रभाव और रोजगार में गिरावट के बावजूद मजदूरी में अनुचित वृद्धि का दोष आयात पर नहीं दिया जा सकता है।
- XVI. जैसा कि इस प्राधिकारी द्वारा अन्य जांच में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी का यह प्रयास है कि पाटन रोधी शुल्क को 10 वर्षों की अविध से आगे तक जारी नहीं रखा जाये। तथापि, वर्तमान समीक्षा में पाटन रोधी शुल्क 17 वर्षों से अधिक समय तक लागू रहा है। प्राधिकारी को अपने निजी सिद्धांत का पालन करते हुए संबद्ध वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करनी चाहिए।
- XVII. एन बी आर 2255 कच्चा माल के उपयोग, अंतिम उपयोग आदि के संबंध में एन बी आर के सामान्य प्रकार से अलग है, प्राधिकारी को सामान्य मूल्य की गणना से एन बी आर 2255 को निकाल देना चाहिए।
- XVIII. सामान्य मूल्य की गणना करते समय, प्राधिकारी को बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों की गणना करने में ब्याज राजस्व को शामिल करना चाहिए।
- XIX. प्राधिकारी को स्व-उत्पादित ब्टाडीन की निर्माण लागत के लिए ब्टाडीन के प्रयुक्त खरीद मूल्य से लाभ को घटा देना चाहिए।
- 76. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए तथा इस प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई अनुरोध निम्नलिखित हैं :
 - I. निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग लेते समय अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है।
 - II. निर्धारित पाटन मार्जिन की मात्रा बह्त ही कम है।
 - III. हानि रहित मूल्य का निर्धारण वास्तविक लागत पर विचार करने के बाद किया जाये जहां आदर्शत्मक उत्पादन के आधार पर निर्धारित खर्चों को बांटा जाता है।
 - IV. घरेलू उद्योग को पाटन रोधी श्ल्क के समाप्त होने की स्थिति में हानि होने की संभावना है।
 - V. पाटन रोधी शुल्क को बढ़ी हुई मात्रा में जारी रखे जाने की आवश्यकता है।
 - VI. श्ल्क की सिफारिश यू एस डालर में निर्धारित राशि के आधार पर की जाये।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियां/ अनुरोध अधिकांशतः दोहराये गये हैं और उनकी जांच पहले ही उपयुक्त रूप से की गई है तथा इस निष्कर्ष के संगत पैराओं में समुचित रूप से उसका समाधान किया गया है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई तथा इस प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों/ टिप्पणियों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है:
 - इस अनुरोध के संबंध में कि इस प्राधिकारी द्वारा प्रकटन टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, सही नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी जांच समयबद्ध होती हैं और प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय दिया गया है। वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी प्रकटन पश्चात टिप्पणियां दायर की हैं।

- श. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच मौजूदा पाटन रोधी शुल्कों के समाप्त होने के बाद अनुचित रूप से तथा गैर कानूनी रूप से शुरू की गई थी और इसे प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अनुरोध की जांच और इसका समाधान इस निष्कर्ष के संगत पैराओं में पहले ही किया जा चुका है तथापि, प्राधिकारी एक बार फिर यह नोट करते हैं कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रारंभन को वैध और कानूनी करार दिया है।
- III. इस तर्क के संबंध में कि कुम्हों का विचार जाने बिना मासिक आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में कुम्हों के अलावा अन्य हितबद्ध पक्षकार है, जिन्होंने पाटन मार्जिन तथा हानि के मार्जिन का मासिक विश्लेषण का अनुरोध प्रमुख कच्चा मालों की कीमतों में भारी अंतर से उत्पन्न एन बी आर की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव के कारण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अनुरोध की जांच और इसका समाधान इस निष्कर्ष के संगत पैराओं में पहले ही किया जा चुका है तथापि, प्राधिकारी एक बार फिर यह नोट करते हैं कि प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में भारी अंतर से उत्पन्न एन बी आर की कीमतों में व्यापक उतार चढ़ाव तथा इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए, प्राधिकारी ने मासिक विश्लेषण करना उपयुक्त माना है।
- IV. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्क वापसी समायोजन की अनुमित इस प्राधिकारी द्वारा निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य के बीच एक उचित तुलना करने के लिए दी गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दावा निर्यातकों द्वारा मौके पर सत्यापन करने के दौरान किया गया था। हालांकि, निर्यातकों ने समर्थक दस्तावेजी प्रमाण के साथ अपने दावों को सिद्ध करने में असफल रहा और निर्यात किए गये उत्पादों में उपभोग की गई सामग्री तथा भुगतान किए गए शुल्क तथा शुल्क वापसी की गणना की पद्धित के बीच संबंध को तार्किक रूप से दर्शाने में असफल रहे हैं। निर्यातक सत्यापन रिपोर्ट पर ही कोई टिप्पणी नहीं दे सके। इसको देखते हुए प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं मानते हैं कि इस संबंध में निर्यातकों के दावे को स्वीकार किया जाये।
- V. इस अनुरोध के संबंध में कि सामान्य मूल्य की गणना करते समय, को व्यापार समायोजन किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस दावे को मौके पर सत्यापन के दौरान निर्यातकों द्वारा उठाया गया था। निर्यातकों ने इस आधार पर व्यापार समायोजन के स्तर का दावा किया था कि जबकि निर्यात बिक्री में एक कमीशन एजेंट शामिल होता है जो कार्य के विभिन्न मदों को करता है और उसे निर्यात मूल्य से कटौती के रूप में दावा किया गया था परंतु कार्य के उन मदों को करने के लिए किए गए खर्च को घरेलू बिक्री कीमत से कटौती नहीं की गई थी। हालांकि, जैसा कि सत्यापन रिपोर्ट में पहले ही दर्शाया गया है, कम्पनी तार्किक रूप से समर्थक दस्तावेजी प्रमाण के साथ समायोजन के दावे का उल्लेख नहीं कर सकी और इसने सत्यापन रिपोर्ट में भी कोई टिप्पणी नहीं दी। इसको देखते हुए प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं समझते हैं कि वह इस संबंध में निर्यातक के दावे को स्वीकार करे।
- VI. इस अनुरोध के संबंध में कि एक वर्ष से आगे अंतिम समीक्षा को जारी रखना गैर कानूनी है और इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, प्राधिकारी नोट करते है पाटन रोधी नियमावली का नियम 23 (3) के साथ पठित नियम 17 के संबंध में, केंद्र सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में अपने विवेक से पाटन रोधी जांच जिसमें समीक्षा जांच भी शामिल है, को पूरा करने के लिए एक वर्ष के बाद 6 महीने की अविध तक समय सीमा बढ़ा सकता है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने केंद्र सरकार के एक वर्ष से आगे 6 महीने के लिए

- जांच को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के निर्णय को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष च्नौती दी है और यह मामला निपटान के लिए लंबित है।
- VII. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और आयात के अवतिरत मूल्य में कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अविध के दौरान आयात का अवतिरत मूल्य पाटन रोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी घरेलू के बिक्री मूल्य से कम है, जिसके फलस्वरूप मूल्य में बहुत अधिक कटौती हुई।
- VIII. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास क्षमता भारतीय बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, प्राधिकारी इसे दोहराते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन रोधी कानून के अंतर्गत संरक्षण के लिए पात्र बनाए जाने के उद्देश्य से इस देश में समग्र मांग को पूरा करने के लिए अधिकार देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, पाटन रोधी उपायों को लगाने से आयात पर रोक नहीं लगती है।
- IX. इस अनुरोध के संबंध में कि हानि रिहत मूल्य की गणना करते समय घरेलू उद्योग का नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमित देना उचित नहीं है, प्राधिकारी दोहराते हैं कि नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की अनुमित देना डी जी ए डी में एक सतत प्रथा है।
- X. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि स्थिर पिरसंपित्तियों में गिरावट आने के बावजूद, हास की लागत में सतत और पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह स्थिति आधार वर्ष की तुलना में उत्पादन में गिरावट के कारण है। क्षमता का उपयोग जांच की अविध के दौरान 94 प्रतिशत से घटकर 67 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, यह नोट किया जा सकता है कि एन आई पी की गणना करते समय, हास और अन्य स्थिर लागतों को नियमावली के अनुबंध ।।। की शर्तों के संबंध में उच्चतम प्राप्त क्षमता उपयोग अर्थात 94 प्रतिशत पर लिया गया है।
- XI. आयात आंकड़ों पर विश्वास किए जाने संबंधी इस अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में डी जी सी आई एंड एस द्वारा दिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। हालांकि, जांच की अविध के लिए प्राधिकारी ने सहयोगी निर्यातकों के सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया है क्योंकि उसकी मात्रा और मूल्य अपेक्षाकृत अधिक पाया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए डी जी सी आई एंड एस स्रोत से लेन-देन वार आयात आंकड़े सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराये गये हैं।
- XII. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को हानि के विश्लेषण में रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयात को लेना चाहिए क्योंकि न्यूनतम स्तर से अधिक था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपलब्ध सूचना के अनुसार रूस का मूल्य कोरिया के मूल्य की त्लना में अधिक है।
- XIII. इस अनुरोध के संबंध में कि सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई डी जी सी आई एंड एस का लेन-देन वार आयात आंकड़ों में अनेक विचाराधीन गैर उत्पाद शामिल हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा और मूल्य पर ही विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।
- XIV. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग के लाभ और घाटे के बीच जांच की अविध के दौरान कोई संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अविध के दौरान घरेलू उत्पादक को आयातित मूल्य के अनुरूप बनाने के लिए बिक्री मूल्य में कटौती करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप मूल्य में कटौती में कमी और घाटे में वृद्धि हुई।
- XV. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी इस बात की भी जांच करने में असफल रहे हैं कि जबकि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के परिणामी प्रभाव और रोजगार में गिरावट के बावजूद

मजदूरी में अनुचित वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित हानि मानदंडों की जांच की गई है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हानि सिद्ध हो चुकी है।

- XVI. इस अनुरोध के संबंध में कि वर्तमान पाटन रोधी शुल्क 17 वर्षों से अधिक समय से लागू है और इसलिए इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम अथवा पाटन रोधी नियमावली अथवा डब्ल्यू टी ओ करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पाटन रोधी शुल्कों को समाप्त करने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण करता हो। जब तक घरेलू उद्योग को पाटन से हानि होती रहेगी, पाटन रोधी शुल्क लागू रखा जा सकता है ताकि घरेलू उद्योग को पाटित वस्तुओं की तुलना में एक समान अवसर प्रदान किया जा सके।
- XVII. इस अनुरोध के संबंध में कि एन बी आर 2255 एन बी आर के सामान्य प्रकार से अलग है और इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले तथा वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एक्रीलोनिट्राइल बुटाडीन रबइ (एन बी आर) है। अपेक्षित कच्चा माल और विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन की प्रक्रिया वही है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद की विभिन्न श्रेणियां उपयोग के मामले में परस्पर रूप से अनन्य नहीं हैं। उपयुक्त को देखते हुए प्राधिकारी इसे उचित नहीं मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एन बी आर 2255 को निकाल दिया जाये।
- XVIII. इस अनुरोध के संबंध में कि सामान्य मूल्य की गणना करते समय, प्राधिकारी को बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों की गणना करने में ब्याज राजस्व को शामिल करना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कोई कम्पनी एक बहु उत्पाद कम्पनी होती है तब विचाराधीन उत्पाद का इसकी कुल बिक्री में अंशदान बहुत कम होता है। अतः यह उपयुक्त है कि बिक्री अन्पात के आधार पर सकल ब्याज को बांटा जाए।
- XIX. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को स्व-उत्पादित बी डी की निर्माण लागत के लिए बी डी के प्रयुक्त खरीद मूल्य से लाभ को घटा देना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हाउस उत्पादन के लिए ब्टाडीन दरों को अपनाते समय उचित अनुमति दी गई है। अंतरण मूल्य कोरिया से भी अन्य उत्पादक के मूल्य से तुलनीय है।
- XX. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि हानि रहित मूल्य (एन आई पी) का निर्धारण वास्तविक लागत पर विचार करते हुए किया जाए जहां निर्धारित खर्चों का बंटवारा आदर्शतम उत्पादन के आधार पर किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन आई पी का निर्धारण पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध ।।। के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर किया गया है।

ध. <u>निष्कर्ष</u>

- 78. उठाये गये मुद्दों, दी गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में तथा इस निष्कर्ष में रिकार्ड में दर्ज उपलब्ध तथ्यों को प्राधिकारी के समक्ष रखने तथा पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप हानि के जारी रहने की स्थिति तथा पाटन और हानि के जारी रहने/ उसके बार बार होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :
 - कोरिया जन. गण. से संबंधित उत्पाद का सतत पाटन हुआ है, जिससे घरेलू उद्योग को हानि हुई है।
 - ii) मूल्य में कटौती और कम मूल्य में बिक्री दोनों सकारात्मक हैं।
 - iii) घरेलू उद्योग का वित्तीय कार्य निष्पादन और अधिक खराब हो गया है। जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग ने आर्थिक मानदंडों जैसे उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता

का उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में नकारात्मक वृद्धि दर्शायी है। पाटित आयात से घरेलू उद्योग को हानि होना जारी है।

iv) यदि वर्तमान पाटन रोधी शुल्क को वापस ले लिया जाता है तब विचाराधीन उत्पाद का पाटन संबद्ध देश से और अधिक होने की संभावना है।

न. सिफारिशें

- 79. उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, प्राधिकारी का मत है कि पाटन रोधी उपाय को निम्नलिखत तालिका में निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- 80. प्राधिकारी द्वारा अपनाये जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क के नियम के संबंध में प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और हानि के मार्जिन में से जो भी कम है उसके बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 9 में दर्शायी गई राशि के समतुल्य पाटन रोधी शुल्क को संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं	शीर्ष	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	4002	एक्रीलोनिट्राइ ल बूटाडीन रबड़ (एन बी आर)	कोई भी	कोरिया जन.गण.	कोरिया जन.गण.	मैसर्स कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कं. लिमि.	मैसर्स कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स कं. लिमि.	57	मी.ट.	अम.डॉ.
2.	4002	एक्रीलोनिट्राइ ल ब्टाडीन रबड़ (एन बी आर)	कोई भी	कोरिया जन.गण.	कोरिया जन.गण.	मैसर्स एल जी केमिकल्स लिमि. (एल जी)	मैसर्स एल जी केमिकल्स लिमि. (एल जी)	61	मी.ट.	अम.डॉ.
3.	4002	एक्रीलोनिट्राइ ल ब्टाडीन रबड़ (एन बी आर)	कोई भी	कोरिया जन.गण.	कोरिया जन.गण.	उपर्युक्त क्रम सं. 1 उ उत्पादक - निर्यातक अन्य कोई भी उत		85	मी.ट.	अम.डॉ.
4.	4002	एक्रीलोनिट्राइ ल ब्टाडीन रबड़ (एन बी आर)	कोई भी	कोरिया जन.गण.	कोरिया जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	85	मी.ट.	अम.डॉ.
5.	4002	एक्रीलोनिट्राइ ल बूटाडीन रबड़ (एन बी आर)	कोई भी	कोरिया जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोरिया जन.गण.	कोई	कोई	85	मी.ट.	अम.डॉ.

प. <u>आगे की कार्यवाही</u>

81. केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद इस आदेश के विरुद्ध अपील सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अन्रूप सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधीकरण के समक्ष की जाएगी।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2015

FINAL FINDING

Subject:- Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR), originating in or exported from Korea RP.

No.15/29/2013-DGAD: Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

- 2. WHEREAS, the original investigation concerning imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber or NBR (herein after also referred to as the subject goods), originating in or exported from Korea RP and Germany, was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No. 9/1/95-ADD dated 15th March, 1996. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 9/1/95-ADD dated 30th December, 1996 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 9/97-Customs dated 31st January, 1997. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 9/1/95-ADD dated 17th July, 1997, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 62/1997- Customs dated 30th July, 1997 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and Germany.
- 3. WHEREAS, the Authority initiated the first sunset review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and Germany vide Notification No. 50/1/2001 dated 1st October, 2001 and recommended continued imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods vide notification No. 50/1/2001 dated 21st September 2002. The Central Government in the Revenue Department vide notification No. 111/2002- Customs dated 10th October, 2002 notified continued imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and Germany.
- 4. The Authority initiated mid-term review investigations on imports of subject goods exported from Korea RP and Germany on 29th March, 2004 and recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject good vide notification No. 15/5/2004 dated 6th June 2005. The continued imposition of anti-dumping duties were notified by the Central Government vide Notification No.78/2005-Customs dated 1st September 2005.
- 5. Another sunset review investigation was initiated by the Authority vide Notification No. 15/6/2007 dated 8th October 2007 and the Authority recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from Korea RP only vide Notification No. 15/6/2007 dated 4th October 2008 and continued duty was notified by the Central Government vide Notification No. 01/2009-Customs dated 2nd January 2009.
- 6. Whereas, in the present SSR investigation, M/s Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd., filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP (hereinafter also referred to as the subject country) and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from Korea RP.
- 7. In view of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the present sunset review investigation vide Notification No. 15/29/2013-DGAD dated 31st December, 2013 to review the need for continued imposition of the duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country has been extended up to 1st January, 2015 by the Central Government vide Notification No. 06/2014-Customs (ADD) dated 23rd January, 2014.
- 8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. Procedure

- 9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a) The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
 - b) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the

- non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
- c) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known producers/exporters in Korea RP (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):
 - (i) M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd.
 - (ii) M/s LG Chem Ltd.
- d) Response to exporter questionnaire was received from both the producers/exporters from the subject country.
- e) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):
 - (i) Nu-Cork Products Pvt. Ltd.
 - Shaktiman Rub Rolls Pvt. Ltd.
 - (iii) Bony Polymers Ltd.
 - (iv) Unique Rubber Udyog
 - (v) Lakhani Rubber Udyog Ltd.
 - (vi) Alaska Tyres Pvt. Ltd.
 - (vii) Super Seals (India) Ltd.
 - (viii) Roop Rubber
 - (ix) Layallpur Rubber Mills
 - (x) Ferolite Jointings Ltd.
 - (xi) Gates India Pvt. Ltd.
 - (xii) Banco Products (India) Ltd.
 - (xiii) Bharat Corrub Industries
 - (xiv) Champion Jointings Ltd.
 - (xv) Favourite Safety Products
 - (xvi) Grindback
 - (xvii) Industrial Roller Corporation
 - (xviii) Lathia Indl Suppliers Co. Pvt. Ltd.
 - (xix) Polyrub Extruction (India)
 - (xx) Precitex Rubber Ind. P. Ltd.
 - (xxi) Andhra Polymers (P) Ltd.
 - (xxii) Godavari Petro Products (P) Ltd.
 - (xxiii) Galaxy Rubber Products.
 - (xxiv) Sundram Industries Ltd.
 - (xxv) Sundram Brakelining Ltd.
 - (xxvi) Sundaram Auto Components Ltd
 - (xxvii) Suja Rubber Industries Pvt. Ltd.
 - (xxviii) Rane Brakelining Ltd.
- (xxix) MRFLtd.
- (xxx) Lakshmi Machine Works Ltd.
- (xxxi) Industrial Rubber Products
- (xxxii) Habasit Lakola Pvt. Ltd.
- (xxxiii) Elgi Ultra Industries Ltd.
- (xxxiv) M/s.Imperial Rubber Products

- (xxxv) M/s.Jayashree Polymers Pvt. Ltd.
- (xxxvi) M/s. K. D. Joshi
- (xxxvii) M/s. Perfect Oil Seals & I.R.P.
- (xxxviii) M/s. Hindustan Composites Ltd.
- (xxxix) M/s. Inacora Ltd.
- (xl) M/s. Imperial Waterproofing Industries Pvt. Ltd.
- (xli) M/s. Parker Markwel Inds. P. Ltd.
- f) No response to importer questionnaire has been submitted by any of the importers/users.
- g) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review was 1st October, 2012 to 30th September, 2013 (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2010-March 2011, April 2011-March 2012, April 2012-March 2013 and the POI.
- h) The domestic industry had relied upon the DGCI&S published data for imports. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period including the POI and also the post-POI. The Authority has relied upon the transaction-wise imports data provided by DGCI&S in the present investigation. However, for the POI, the Authority has relied upon the verified data of the co-operating exporters since the volume and value of the same was found to be higher.
- Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties.
- j) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
- k) The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Anti-dumping Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if antidumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- 1) In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 9th October, 2014, which was attended by the domestic industry and other interested parties. The parties which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally.
- m) The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority, have been examined and addressed in this finding.
 - n) The Department of Revenue vide their letter No. 354/179/2002-TRU (Pt. V) dated 8th January, 2015 extended the time period up to 30th June, 2015 to complete the investigation.
 - On the spot verification of the information and data submitted by the domestic industry and other interested parties was carried out to the extent deemed necessary.
 - p) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- q) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.
- r) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts were disclosed by the Authority to the known interested parties vide a disclosure statement issued on 22nd June, 2015 and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined and addressed in this finding.
- s) ***in this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- t) The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.56.89 = 1 US\$.

C. Litigation Involved

10. The initiation of the present SSR investigation by the DGAD and the extension of the validity of the relevant anti-dumping duty by the DOR were challenged by Kumho Petrochemicals Co. Ltd. and Fairdeal Polychem Ltd before High Court of Delhi vide WPC No. 1851/2014 and No. 1866/2014 respectively. The Hon'ble High Court in its order dated 11th July, 2014 held inter alia as follows:

"The imperative nature of second proviso to Section 9A (5) leaves no room for doubt that in case the Central Government wishes to extend the levy during the sunset review period, it has to comply with the terms of that provision and do so, before expiration of the original period - which in this case was 01-01-2014. Not having done so, its attempt to levy the duty through the later notification of 23-01-2014 is without authority of law; it is contrary to the terms of proviso to Section 9A (5). The attempt to recover any amounts as duty, therefore, violates Article 265 of the Constitution of India. 27. In view of the above findings, it is held that the initiation of sunset review is valid and legal; however the levy of antidumping duty through the impugned notification of 23-01-2014 is without authority of law. The said notification is declared illegal and hereby set aside. The petitioners are entitled to refund of the amounts paid till date. The writ petitions partly succeed and are allowed to the above extent; there shall be no order on costs."

11. The aforesaid judgment of Hon'ble High Court of Delhi was challenged by the Authority before the Hon'ble Supreme Court vide SLP No. 29268-69 of 2014. The Hon'ble Supreme Court vide its interim order dated 9th March, 2015 has stayed the aforesaid judgment.

D. Scope of Product under consideration and like article Submissions made by the Domestic Industry

- 12. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:
 - (i) The product under consideration in the present investigation is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR). The product under consideration is same as defined in the original and subsequent investigations.
 - (ii) NBR is primarily used where oil resistance, abrasion resistance and heat resistance applications are involved. NBR is widely used in Defence, Automobile, Footwear, Fabrics, Printers, Oil field products industries etc.
 - (iii) Grades of Acrylonitrile Butadiene Rubber are described in terms of acrylonitrile content and mooney viscosity in the rubber. The percentage content of Acrylonitrile and Mooney viscosity in NBR differentiates one grade of NBR with other grade. Indian industry produces equivalent/ comparable of various grades being imported at present from the subject country.
 - (iv) The PUC is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) also known as Nitrile Rubber falling under heading No. 40025900 in Chapter 40 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. However, customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
 - (v) There is no difference in subject goods produced by the petitioner and exported from the subject country. Subject goods produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Subject goods produced by the domestic industry and imported from subject country are like article in accordance with the Rules.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

13. No submission has been made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article.

Examination by the Authority

14. The product under consideration (PUC) in the earlier investigations as well as the present SSR investigation is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR), originating in or exported from Korea RP. NBR is a synthetic rubber copolymer of acrylonitrile (ACN) and butadiene. NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice de-husking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are defined in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content. Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) is classified in Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 under subheading No. 40025900. However, the Customs classification is indicative only and is no way binding on the scope of the present investigation. The present investigation being a sunset review, the PUC remains the same as in the earlier investigations.

E. <u>Domestic Industry and Standing Submissions by the Domestic Industry</u>

- 15. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
 - (i) The petitioner i.e. Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd is the sole producer of NBR in the Country. Thus, production of NBR by Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd constitutes 100% of the total Indian production.
 - (ii) In view thereof, Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd satisfies the requirement of standing to file the present petition and constitutes 'Domestic Industry' within the meaning of the Rules.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

16. No submission has been made by the producers/exporters/importers/other interested parties regarding standing and scope of the domestic industry.

Examination by Authority

- 17. The Authority notes that Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules provides as follows:
 - (b) "Domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'Domestic Industry' may be construed as referring to the rest of the producers"
- 18. The Authority further notes that the application for the present sunset review has been filed by M/s Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd., who is the sole domestic producer of the subject goods in the country. M/s Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd., has also declared that there are no imports of the subject goods by them either directly or through an affiliated company from Korea RP and they are not related to any importer in India or exporter from Korea RP. In view of the above position and having regard to the Anti-dumping Rules, the Authority determines that the M/s Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti-dumping Rules.

F. MISCELLANEOUS ISSUES

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

- 19. Following are the miscellaneous submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties:
 - i. The initiation of the present sunset review is bad in law. The anti-dumping duty on the subject goods expired on 1st January 2014 and the extension of the duty vide notification dated 23rd January 2014 has been held illegal by Hon'ble Delhi High Court. The Petitioner has also not established the material grounds for the extension of the duty. Respondents are participating in this investigation under protest as there is no anti-dumping duty in force. The present investigation was improperly initiated after the expiry of existing anti-dumping duties and merits termination ab-initio.
 - ii. Even though the initiation notification is dated 31st December 2013, however, the sunset review initiation was published or in other words made public only on 6th January 2014. The power to extend the anti-dumping duty is vested in the Central Govt. by way of the second proviso in Section 9A(5) of the Act; however, in this case, no such extension was issued till two months after the expiry of the duty.
 - iii. Despite a clear mandate issued by DGAD that domestic industry seeking initiation of sunset review should file a duly substantiated request at least 90 days prior to expiry of anti-dumping duties, the Petitioner has in the present investigation, submitted a petition for the initiation of the sunset review on 11th November 2013, which is beyond the 90 day time limit granted by DGAD. Therefore, authority should terminate the present sunset review immediately.
 - iv. The anti-dumping duty is in force against Korea for more than 16 years. In line with DGAD's approach in its SSR final findings concerning imports of 'Dry Cell Batteries' from China PR that anti-dumping duties should not normally continue beyond 10 years, the ADD on the imports subject goods from Korea should be discontinued.
 - V. Hon'ble Delhi High Court had set aside the Customs notification of extending the ADD. Kumho has already preferred an SLP challenging the decision to Hon'ble Delhi High Court only with respect to the decision of upholding the initiation of investigation. Therefore the initiation of present sunset review is illegal and cannot be acted upon.
 - vi. The decision of Hon'ble Delhi High Court is binding on DGAD and DGAD cannot act contrary to the decision of Hon'ble Delhi High Court. Thus, in view of the fact that (a) there is no anti-dumping duty

in existence as extension notification has been held illegal by Delhi High Court and (b) the principal notification has also expired, DGAD is thus restrained from making any determination that "expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry". Since anti-dumping duty has already expired, DGAD cannot make any other determination in terms of Rule 23.

vii. Applicant has been getting protection of anti-dumping duty for about 17 years. Applicant has reached a situation, wherein it is totally dependent on anti-dumping duty and will always remain so. Such being the case, where Applicant is inherently incapable of competing, it should seek the protection in any other manner, without affecting importers and other end-users.

Submissions by the Domestic Industry

- 20. Following are the miscellaneous submissions made by domestic industry:
 - i. The contention that the Central Government would not be in a position to extend the anti-dumping duty on receipt of final findings in view of the gap between existing duties and the revised duties is incorrect. Section 9A (5) clearly provides for initiation of investigation before expiry of duty and not "sufficiently before the expiry".
 - ii. Hon'ble High Court has upheld the initiation and, therefore, the Designated Authority is fully justified in recording its final findings.
 - iii. The contention that the domestic industry has been protected for a long period is irrelevant. First of all, imposition anti dumping duty is not a "protection". The purpose of imposition of anti dumping duty is merely to eliminate unfair practice of dumping, if the same is causing or is likely to cause injury to the domestic industry. The duty should remain in force as long as necessary to counteract dumping, which is causing injury.

Examination by the Authority

- 21. The miscellaneous submissions are examined as below:
 - i. It has been contented by the opposing interested parties that the initiation of the present review investigation is bad in law and should be terminated ab-initio as the initiation notification dated 31st December 2013 was made public on 6th January 2014 and the extension of the duty has been held illegal by Hon'ble Delhi High Court in their Judgment dated 11th July, 2014. In this regard, the Authority notes that the Hon'ble Delhi High Court in their Judgment has already held the initiation as valid and legal; but the levy of anti-dumping duty as without authority of law. However the aforesaid judgment of Hon'ble High Court of Delhi was challenged by the Authority as well as domestic industry before the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court vide their interim order dated 9th March, 2015 has stayed the said judgment. Thus, the contention is without any basis.
 - ii. It has been contented by the opposing interested parties that the domestic industry has not filed petition within 90 days prior to the date of expiry of anti dumping duty in terms of the trade notice No. 2/2011 dated 6/6/2011. In this regard, the Authority notes that the provisions of Rule 23(1)(B) of Antidumping Rules requires the Designated Authority to consider a petition received for review and extension of anti dumping duty within a reasonable period of time prior to the expiry of that period. The reasonable period of time requirement provided under the Rules is a provision intended to grant sufficient time to the Authority to consider an application and not to bar the Authority to consider an application beyond that period. In the present case the facts of the delay in filing application by the domestic industry was examined by the Authority while initiating the investigation. The fact that the investigation has been initiated by the Authority should be enough to treat that the delay has been condoned by the Authority.
 - iii. The contention that the anti-dumping duty is in force against Korea for more than 16 years and therefore, it should be discontinued has no legal basis. The Authority notes that there is no provision under the Customs Tariff Act or the Anti-dumping Rules or the WTO Agreement prescribing any time frame for discontinuation of anti-dumping duty. As long as there is dumping causing injury to the domestic industry, anti-dumping duties can be in force to provide a level playing field to the domestic industry vis-à-vis dumped goods.

G. Confidentiality

Submissions made by exporters/importers/users/other interested parties

- Following are the submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality:
 - i. The present petition suffers from excessive confidentiality.

 Transaction by transaction import statistics has not been made available. Without the import statistics, it is not possible to determine with accuracy whether the claims regarding effects of imports have been given correctly or not.

Submissions made Domestic Industry

- 23. Following are the submissions made by domestic industry with regard to confidentiality:
 - i. The exporters have resorted to excessive confidentiality in the questionnaire response filed by them.
 - Excessive confidentiality claimed by the respondent producers/exporters completely prevented the domestic industry from defending its interests.
 - iii. The non-confidential transaction-wise DGCI&S import data furnished by the domestic industry to the Authority may be placed in the public file.

Examination by the Authority

- 24. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
 - i. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-
 - Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied asto its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.
 - (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that there quest for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.
 - ii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
 - iii. As regards the contention that transaction by transaction import statistics has not been made available to interested parties, the Authority notes that domestic industry has already placed the transaction by transaction DGCI&S import statistics in public file.

H. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

- 25. Following are the submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin
 - i. In the previous sunset review investigation, Kumho's dumping margin was a mere ***%. During the POI of present investigation, there is no dumping by Kumho.
 - ii. Kumho exported a mere ***% of its total sales of subject goods to India. The allegation that Kumho has made misleading statements about its exports into India is wrong.
 - iii. Kumho is operating in a market economy country and thus has claimed normal value based on prices in its domestic market. Kumho has provided all the information to the extent relevant in the manner and form prescribed in line with the accounting standards of Korea.
 - iv. The submission made by the Applicant that DGAD should verify the consumption factors and compare the same with consumption reported by Applicant makes no sense. DGAD has to only go by the consumption norms given by Kumho and accept the same if found reliable. There is no legal basis for comparing the same with Applicant's consumption norm.

- v. During the period of investigation LG Chem Ltd., Korea RP, has exported negligible quantities and could not have caused injury to the domestic industry.
- vi. The estimation of normal value and export price by Petitioner is faulty and illegal. While normal value has been determined based on Petitioner's own prices, which is not mandated under the law in case of market economy countries, export price has been determined by making undue and unsubstantiated adjustments. Thus, the dumping margin arrived at by Petitioner for claiming continued dumping is flawed.
- vii. The Domestic Industry has claimed a dumping margin of 23%. The same is based on the inflated normal value claimed by the Domestic Industry.
- viii. In the previous investigation, Authority rejected the request of Kumho to determine dumping margin on month-wise analysis and instead Authority determined dumping margin based on weighted average basis for the POI. Therefore, Authority is requested to determine dumping margin in this investigation on weighted average basis for the entire period of POI.

Submissions by Domestic Industry

- 26. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:
 - i. Kumho stated that their exports have shown hardly 5-8% increase over the period. LG Chem stated that their exports in Indian market were negligible. On the contrary, imports have increased from about 419 MT in 1992-93 to 13,322 MT in 2013-14 and Korea is the majority supplier of the product in the Indian market. The volume of imports from Korea, which were merely in the region of 400 MT in 1992-93 (base year of original investigation) have increased to a whopping 14,000 MT. This has been only because of dumping resorted by the exporters.
 - Authority should examine the transaction-wise exports data in respect of third countries, if provided by the respondent exporters. Otherwise, the questionnaire responses should be considered as incomplete and rejected.
 - iii. KPC purchased the raw materials from unrelated companies. However, KPC has also produced the butadiene and used it for the production of the product concerned. This aspect needs to be focussed by the Authority. The Authority must investigate the exporters' data thoroughly considering the complexity of the in-house consumption of inputs, such as transfer pricing and related party transactions.
 - iv. The dumping margins determined by the Authority in the previous investigations are too low, considering the prices of inputs, factors of production and minimum costs that must be incurred by a producer in producing and selling the product. Cost of production that should be determined and considered should be the cost that is ordinary cost and not special cost. Such costs must reflect intrinsic value of the materials.
 - v. The elements of costs, even though might be based on the records kept by the exporter, nevertheless does not imply that the Designated Authority is bound to adopt the cost of production of the exporter without satisfaction whether the same reasonably reflect the cost associated with production and sale of the product under consideration. Such costs should reasonably reflect the costs associated with production and sale of the product under consideration.
 - vi. The determination of dumping margin for Korean companies in the present product has remained an issue of significant dispute. The domestic industry has all along been contending that the dumping margins determined are grossly low considering reasonable estimates of cost of production for the product under consideration. The captive input consumed by the exporter is required to be taken at their market value.
 - vii. The dumping margin in respect of the subject country is quite significant. Existence of significant dumping is a clear evidence of continued injury being caused to the domestic industry.
 - viii. The exporters and producers from the subject country have continued to export the material at the dumped prices even after the imposition of the anti-dumping duty. Given that the dumping has consistently continued from the subject country in the past, there is no reason to consider that cessation of duties in the present case would not result in intensified dumping from this source.

Examination by the Authority

27. The facts of dumping analysis ipso facto address the various submissions made by the interested parties. The Authority notes that the information/data furnished by the respondent cooperative producers/exporters from Korea RP has been verified and the normal value, export price and dumping margin has been determined as follows:

Determination of Normal Value

28. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

- (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
- (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - (a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

- 29. Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) is a synthetic rubber copolymer of acrylonitrile (ACN) and butadiene. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are defined in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content. NBR of various grades is produced and sold both in domestic and export markets. Though there are numerous PCNs depending upon the mooney viscosity and acrylonitrile content suitable for various applications, but the main cost driver in NBR is the composition of Butadiene and acrylonitrile monomers in the final product. Based on the contents of ACN, the product is broadly classified into three grades having 36%-45% (High), 31%-35% (Medium) and 26%-30% (Low) contents of ACN. The share of Medium ACN grade in production and domestic sales is 75%-80% and export of this particular grade to India from both the cooperating exporters during POI was around 95%. Moreover, the comparison of raw material cost in each of these grades demonstrated that the variation from the medium ACN grade was 1%-1.5% only. Keeping in view these facts, the Authority does not consider it appropriate to determine grade- wise normal value. Instead, considering the wide fluctuation in the prices of the major raw materials and as submitted by the interested parties, the Authority considers it appropriate to determine the normal value on monthly basis and determine the net export price and dumping margin accordingly. As per the practice in DGAD, after applying the 80/20 test, the domestic unit sales price of each month has been compared with the average unit cost for the corresponding month and the domestic ex factory price of profit making transactions have been adopted as normal value.
- 30. The following producers/exporters from Korea RP have filed exporter's questionnaire response:
 - i. Kumho Petrochemical Co. Ltd. (KPC)
 - ii. LG Chem Ltd. (LG)

Kumho Petrochemical Co. Ltd. (KPC)

31. In the present investigation, Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea RP (producer/exporter) had filed exporter's questionnaire response. During the verification, it was informed that with effect from 14th March 2008 the name of the Company has been changed from "Korea Kumho Petrochemicals Co Ltd" to "Kumho Petrochemicals Co Ltd". During the POI, KPC sold *** MT of subject goods in the domestic market for a total ex factory value of KRW ***. All the domestic sales were made by KPC to unrelated parties. The Authority made month-wise analysis of the transactions and applied ordinary course of Test. After making due adjustments on account of packing expenses, inland freight and credit expense, the Authority has determined the normal value for KPC as US\$ ***per MT.

LG Chem Ltd. (LG)

32. In the present investigation, LG Chem Ltd., Korea RP (producer/exporter) had filed exporter's questionnaire response. On the basis of verified information/data, during the POI, LG made ***MT of domestic sales of subject goods worth of KRW *** and USD ***. Out of the total domestic sales of subject goods, about 0.18% was sold to affiliated parties and the balance 99.82% was sold to non-affiliated parties. Since the average sales realization from sales made to the affiliated parties was not less than other non-related parties, the same have not been ignored. Further, information furnished in Appendix 1 to the questionnaire response, the company had included NBR powder also which is not part of subject goods and the same has been excluded for the purpose of working out normal value. As such domestic sales of ***MT with ex-factory value of *** KRW (*** USD equivalent). The Authority made month-wise analysis of the transactions and applied ordinary course of Test. After making due

adjustments on account of packing expenses, inland freight and credit expense, the Authority has determined the normal value for LG as US\$ ***per MT.

Determination of Normal Value for all other exporters

33. The Authority notes that apart from the above stated exporters, no other exporter/producer from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers of the product under consideration in Korea RP, the Authority has determined the normal value on the basis of best available information as ***US\$/MT.

Export Price

Kumho Petrochemical Co. Ltd. (KPC)

34. During the POI, KPC had exported ***MT of the product under consideration to India for a total value of USD ***. Almost ***% of the exports of the product under consideration to India comprised of the Medium grade. After making the due adjustments on account of packing expenses, inland freight, ocean freight, ocean insurance, port handling charges, customs brokers fee, credit expense, bank charges and sales commission, the Authority has determined the net export price of KPC as US\$ ***per MT during the POI.

LG Chem Ltd. (LG)

35. During the POI, LG exported ***MT of product under consideration to India worth of US\$ ***. Almost 95% of the exports of the product under consideration to India comprised of the Medium Grade. This also included a small quantity of indirect exports for which the response to the questionnaire has not been filed by the exporter/importer. Therefore, only direct exports of ***MT have been considered for the purpose of calculation of Net Export Price. After making due adjustments on account of packing expenses, inland freight, ocean freight, ocean insurance, customs agent fee, credit expense, bank charges and sales commission, the Authority has determined the net export price of LG as US\$ ***per MT during the POI.

Determination of Export Price in respect of Non-Co-operative Exporters/Producers from Korea RP

36. In respect of all other exporters from Korea RP who are treated to be non-cooperative, the Authority has determined their net export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules as US\$ ***per MT.

I. Dumping Margins

37. Considering normal value and export price at ex-factory level as determined above, the dumping margin for all the producers/exporters in the subject country has been determined by the Authority as follows:-

		KPC	LG	Others
Normal value	US\$/MT	***	***	***
Net Export price	US\$/MT	***	***	***
Dumping Margin	US\$/MT	***	***	***
Dumping Margin as a Percentage of net Export Price (NEP)	%	***	***	***
Dumping Margin	Range %	0-10%	0-10%	0-10%

J. <u>Methodology for Injury Determination and Examination of Injury and Causal Link</u> Submissions by the domestic industry

- 38. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:
 - i. The fact that the consumption in India is higher than the capacities with the Indian producer may justify imports per se. The same, however, does not justify dumping. There is no reason/occasion for the foreign suppliers to resort to dumping to meet Indian demand. In view of inevitable imports into the Country, the domestic industry is forced to set its prices considering the price offers of the leading foreign suppliers and disregard its cost consideration. Since the foreign producers are resorting to dumping, the domestic industry is forced to follow such dumped prices.

- ii. The volume of imports from the subject country has increased in absolute terms throughout the injury period despite anti-dumping duty in existence. This clearly evidences that the present anti-dumping duty is inadequate to curb the dumped imports from the subject country.
- iii. The landed price of imports was substantially below the selling price of the Domestic Industry. The imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market. The landed price of imports from the subject country is also far lower than the cost of sales and NIP of the domestic industry.
- iv. The landed price of imports is significantly below the cost of production of the domestic industry throughout the injury period signifying price suppression. Imports have also significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The effect is such that the domestic industry was compelled not to increase their price in proportion to increase in cost of sales, thereby, suffering huge financial losses.
- v. While cost of production and selling price increased in 2011-12 and thereafter in 2012-13. However, the selling price declined in 2012-13 when the cost of production increased. Even though in POI, the cost of production declined to some extent, the decline in the selling price in 2012-13 and POI was still too significant than the decline in cost of production. It is, thus, evident that the effect of dumped imports on the domestic industry has been adverse and significant.
- vi. The production of the petitioner and capacity utilization declined throughout the period. The sales of the domestic industry also declined throughout the period. The adverse situation of the domestic industry is despite (a) anti-dumping duty in existence, (b) demand for the product far beyond the capacities with the domestic industry. This shows that the anti-dumping duty imposed is inadequate.
- vii. The domestic industry could make some profits in 2011-12 and then suffered significant financial losses. As a result of decline in profitability, the domestic industry has suffered cash losses and negative return on investment.
- viii. Average inventory levels of the domestic industry have declined. This is because the domestic industry has been regulating the inventories and production is being undertaken considering the sales volumes.
- ix. Employment level has declined over the injury period. However, there has been an increase in the wages.
- x. Productivity of the domestic industry has declined over the injury period in tandem with the decline in production. Should the anti dumping duty on the product be removed, productivity of the domestic industry would suffer further.
- xi. Consideration of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from subject country is below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market and imports of subject goods from other countries are at much higher prices.
- xii. Demand for the subject goods was showing significant increase and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the major factor responsible for the domestic industry's prices is the landed price of the subject goods from subject country and the cost of production of the domestic industry.
- xiii. There is positive and significant increase in demand of product in India. Capacity of domestic industry is lower than demand, despite which the sales volumes of the domestic industry declined due to presence of dumped imports in the Indian market. On the other hand, volume of dumped imports from the subject country has increased significantly over the injury period.
- xiv. The growth of the domestic industry in terms of sales, production, capacity utilization, market share, profits, return on investment and cash profits was negative. This is clearly due to continued dumping of the product under consideration in the market.
- xv. Continuous adverse performance of the product due to persistent Korean dumping has prevented the domestic industry from moving further on the capacity expansion.
- xvi. Domestic Industry is suffering continued injury because of dumped imports of subject goods. Further, the Domestic Industry is yet to earn reasonable rate of return. Above all, the

- domestic industry is not able to fully utilize its capacities despite significant and sufficient demand in the Country.
- xvii. Imports from subject country are causing severe price undercutting to the Domestic Industry. Should the present anti dumping duty cease, there is a clear likelihood that price undercutting would increase further.

Submissions by producers/exporters/importers other interested parties

- 39. The following injury related submissions have been made by producers/exporters/importers other interested parties:
 - There is no correlation with prices of imports of subject goods and selling price of domestic industry.
 - ii. Capacity of domestic industry is insufficient to meet the demand of the Indian market.
 - iii. There seems to be a big anomaly between the trend of fixed assets and trend of depreciation provided by the Petitioner. While fixed assets of Petitioner have declined consistently throughout the injury period, depreciation has consistently gone up.
 - iv. Domestic industry's claim for 22% return on capital employed is undue and baseless.
 - v. Contrary to the analysis of Applicant that imports have increased substantially in comparison to production, it is the other way round as it is the production, which has declined substantially with increase in imports remaining more or less stable. Had it been only increase in subject imports, then the same would have shown a substantial increase in comparison to total imports as well.
 - vi. Applicant has computed landed value incorrectly by adding basic customs duty and customs cess to CIF value instead of assessable value. This has deflated the landed value and rendered the entire price effect incorrect.
 - vii. Two mid-term reviews and two sunset reviews have already been conducted, wherein dumping margin was lower than the injury margin. This implies that there were other reasons apart from dumping of subject goods, which resulted in injury to the domestic industry.
 - viii. Dumping and injury margins should be determined on monthly basis due to wide fluctuation in the prices of NBR caused by wide variation in the prices of the major raw materials

Examination by the Authority

- 40. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties, and considered relevant, are addressed by the Authority as below:
 - i. As regards the submission that capacity of domestic industry is insufficient to meet the demand of the Indian market, the Authority notes that there is no legal provision mandating the domestic industry to meet the entire demand in the country.
 - ii. As regards the submission that 22% return on capital employed, allowed by DGAD, is not reasonable, the Authority notes that granting 22% return on capital employed is a consistent practice in the DGAD.
 - iii. As regards the contention that while fixed assets of petitioner have declined consistently throughout the injury period, depreciation has consistently gone up, the Authority notes that the non-injurious price of the domestic industry has been determined in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules.
 - iv. As regards the submission that dumping and injury margins for period of investigation should be determined on monthly basis due to wide fluctuation in the prices of NBR caused by wide variation in the prices of the major raw materials, the Authority notes that dumping margin and injury margin have been determined on monthly basis.
- 41. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
- 42. Rule 11 of Anti-dumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the

- like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 43. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
- 44. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from Korea RP are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing anti-dumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.
- 45. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- 46. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Omnova Solutions (India) Pvt. Ltd., constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows

VOLUME EFFECT

Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry

Demand and Market Share

47. The Authority notes that the import volume and value as reported by the cooperative exporters from the subject country for the POI is more than that reported in the DGCI&S data by *** MT. In view of this, the Authority has accepted the import volume and value reported by the cooperative exporters for the POI. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the Indian producer and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table given below. The Authority notes that demand for the product under consideration in the country has increased consistently throughout the injury period including the POI. Further, while the imports from subject country have also increased in line with the domestic demand, the sales of the domestic industry have declined. The Authority further notes that the market share of the domestic industry has declined over the injury period, whereas market share of the subject country as well as imports from other countries increased during the POI as compared to the base year.

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Demand	MT	24,300	25,751	31,961	33,691
Trend	%	100	106	132	139
Imports - Korea RP	MT	7,596	7,808	11,187	13,585
Imports - Other countries	MT	8,657	10,605	14,493	14,079
Sales of Domestic industry	MT	8,047	7,338	6,281	6,027
Market Share					
Subject imports	%	31	30	35	40
Other imports	%	36	41	45	42

Domestic industry	%	33	29	20	18	
Domestic madsay	70	33	27	20	10	

Import Volume & market share

48. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Korea RP	MT	7,596	7,808	11,187	13,585
Other Countries	MT	8,657	10,605	14,493	14,079
Total Imports	MT	16,253	18,413	25,680	27,664
Imports from Subject cour	ntry in relati	on to			
Total Imports	%	47	42	44	49
Consumption in India	%	29	29	34	39
Production in India	%	80	91	153	191

49. The Authority notes that the volume of imports from the subject country is significant. Further, the imports from the subject country vis-à-vis domestic demand and production have increased during the POI as compared to the base year.

PRICE EFFECT

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

50. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of Annexure III of the Antidumping Rules. The position is as follows.

Price Undercutting and Underselling

51. The Authority has made price undercutting and price underselling analysis both with and without anti dumping duty as below:

Price Undercutting

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	123	111
Landed Price – Korea RP	Rs./MT	1,38,151	1,82,931	179,736	1,49,123
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting %	%	***	***	***	***
Price Undercutting %	Range	10-20%	10-20%	5-15%	10-20%
With anti dumping duty					
Landed Price – Korea RP	Rs./MT	1,39,999	1,84,986	1,81,704	1,51,289
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting %	%	***	***	***	***

Price Undercutting %	Range	10-20%	10-20%	5-15%	5-15%

Price Underselling

Particulars	Unit	POI
Non injurious Price of Domestic industry	Rs./KG	***
Landed Value	Rs./KG	1,49,123
Price Underselling	Rs./KG	***
	%	***
	Range%	10-20

52. The Authority notes that landed price of imports is below the selling price of the domestic industry even after adding anti-dumping duty, resulting in significant price undercutting. Further, price underselling effect is also significant.

Price Suppression and Depression

53. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with that of cost of sales. The given data shows that the domestic industry's selling price has remained below its cost of sales throughout the injury period except in 2011-12, signifying existence of price suppression effect.

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	%	100	126	134	115
Net Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	%	100	136	123	111

K. Examination of other economic parameters of the domestic industry

54. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are analysed below.

Sales, Production, capacity and capacity utilization

55. The Authority notes from the table below that the production, sales and capacity utilization of the domestic industry declined over the injury period, despite increase in demand in the country and continued imposition of anti-dumping measures.

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity	MT	11,000	11,000	11,000	11,000
Production	MT	10,349	9,196	7,874	7,390
Capacity utilization	%	94	84	72	67
Domestic sales	MT	8,047	7,338	6,281	6,027
Demand	MT	24,300	25,751	31,961	33,691

Profit/loss, return on investment and cash flow

56. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	126	134	115
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	136	123	111
Profit/loss	Rs./MT	(***)	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	28	(264)	(144)
Profit/loss	Rs. Lacs	(***)	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	25	(201)	(103)
Profit before interest & tax	Rs. Lacs	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	22583	(17507)	(8242)
Cash Profit	Rs. Lacs	(***)	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	78	(210)	(82)
Return on Investment	%	***	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	884	(957)	(430)

57. The Authority notes that the cost of sales increased up to 2012-13 and then declined in the POI. The selling price increased up to 2011-12 and then declined in 2012-13 and the POI. The domestic industry could make some profits in 2011-12 and then suffered significant financial losses. As a result of decline in profitability, the domestic industry has suffered cash losses and negative return on investment.

Inventories

58. The data given in the table below shows that the inventory of the subject goods of the domestic industry declined during the POI as compared to the base year. Keeping in view the fact that demand in India exceeded the supply, the inventory position of the company was substantial.

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85	84	77

Employment and wages

59. From the table given below, the Authority notes that the employment level of the domestic industry has declined during the POI as compared to the base year. It is, however, noted that the wages have increased.

Period	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	%	100	100	95	90
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	%	100	128	162	163

Productivity

60. The Authority notes from the table below that productivity of the domestic industry during POI has declined as compared to the base year.

Productivity	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	%	100	89	80	79
Per Day	MT	29.57	26.27	22.50	21.11
Trend	%	100	89	76	71

Factors affecting prices

61. The examination of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc shows that both with and without the anti-dumping duty, the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price undercutting as well as under selling effects. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the POI and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is the landed value of subject goods from the subject country.

L. Magnitude of Dumping Margin

The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive and significant.

M. Growth

63. The Authority notes that the domestic industry has shown negative growth in terms of all economic parameters such as production, domestic sales, capacity utilization, market share in demand, profit, cash profit, ROCE, etc. throughout the injury period.

Growth % (Year by Year)	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Production Volume	%	-	(11.14)	(14.38)	(6.15)
Domestic Sales Volume	%	-	(8.82)	(18.98)	(3.61)
Cost of Sales	%	-	25.08	6.46	(13.93)
Selling Price	%	-	36.10	(9.38)	(9.95)
Profit/Loss	%	-	125	(896)	49
Return on Capital	%	-	14	(26)	6
Employed					

Ability to raise Capital Investment

64. The Authority notes that in view of continuous dumping of subject goods from the subject country causing continued material injury, it is obvious that the domestic industry cannot contemplate for fresh investments.

N. Causal Link

- 65. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:
 - Imports from Third Countries: The Authority notes that the average price of imports of product under consideration from other countries is higher than that of the subject country during the POI, and therefore, could not have caused injury to the domestic industry.
 - ii. Contraction in Demand: The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has consistently increased throughout the injury period.
 - iii. **Pattern of consumption**: It is noted that no significant change in the pattern of consumption for the subject goods has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission in that regard.
 - iv. Conditions of competition: The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.
 - Developments in technology:- The Authority notes that the investigation has not shown that there
 was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.
 - vi. Export performance of the domestic industry: The export performance of the domestic industry is not relevant since price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

O. <u>Likelihood of dumping and injury</u>

Submissions by the domestic industry

66. Following are the submissions made by the domestic industry:

- i. There are continued dumping of the subject goods from the subject country and consequently continued injury to the domestic industry despite anti-dumping duty in existence. Despite imposition of anti-dumping duty (ADD) against imports from the subject country, domestic industry continues to suffer injury because of the constant presence of the dumped imports in the Indian market. This clearly leads to an implication of likelihood of injury to the Domestic Industry.
- ii. The present anti-dumping duty in place is significantly low. Import price from the subject country **remained** lower than the cost and selling price of the domestic industry, as the exporters increased their prices much less than the increase in costs due to raw materials price increase. Where raw material prices registered decline, the same was reflected in the export price. Thus, the quantum of measures imposed has failed to protect the domestic industry from unfair competition from subject imports.
- iii. The volume of imports from the subject country has in fact increased when compared to the injury period of original investigations. One of the purposes of anti-dumping duties is to eliminate dumping and to restore a situation on fair market conditions. If there had been no continued dumping of the product, imports would have declined. Continued presence of dumped imports, in fact, in higher volumes, is due to continued dumping of the product in the country and not due to fair business practices. While the domestic industry is trying to come out of the ill-effects of dumping, it continues to suffer injury in view of continued dumping of the product in the country.
- iv. Dumping margin determined in the present investigation is higher than that of previous investigations and significant which clearly shows likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti dumping duty. This clearly establishes that the dumping is likely to continue and indeed intensify in the event of cessation of present anti dumping duty.
- v. The market share of imports from the subject country is quite significant in spite of the existing antidumping duties.
- vi. Producers in the subject country maintain huge capacities to produce NBR, far beyond domestic demand. In case of cessation of the present duty, dumping from subject country would definitely continue and in fact intensify and ultimately cause intensified volume and price injury to the Domestic Industry.
- vii. The Indian market is highly price sensitive. In the event of cessation of current antidumping duty, the domestic industry will have to further reduce the price or loose significant sales volumes. In the event of cessation of current anti-dumping duty and if Domestic Industry chooses to sell at import prices, the Domestic Industry would suffer further decline in profitability.
- viii. Imports from subject country are undercutting and would continue to undercut the prices of the Domestic Industry, should the present anti dumping duty be removed. The Indian prices are quite lucrative to the foreign producers and would further lead to increase in imports.
- ix. It is not necessary that all conditions should exist for continuation of duty. Even if one or more parameters are satisfied, the anti-dumping duty should be continued.
- x. The responding exporters in the subject country must establish that dumping is unlikely to continue in the event of revocation of anti-dumping duty. Unless the exporters establish on the basis of information that dumping is unlikely to continue or intensify in the event of expiry of anti-dumping duties, the Designated Authority must hold that dumping would continue and intensify in the event of cessation of anti-dumping duties causing consequent injury to the domestic industry.
- xi. The causal link has already been established in all the previous investigations. In the present sunset review investigation, the Designated Authority has to examine whether cessation of anti dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury. However, there exists a causal relationship between the likelihood of dumping and consequent injury.
- xii. The present injury to the domestic industry is because of dumped imports in India. This is clearly established by significant price undercutting, price underselling, price depression/suppression, increase in import volumes in absolute terms & in relation to production & consumption in India, decline in production, sales, market share, profits, cash flows and return on investment. The deterioration in performance of the domestic industry is due to dumped imports in the Country.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

- 67. The responding opposite interested parties have made the following submissions:
 - Kumho is already operating at more than optimal capacity utilization. As a result, even if a
 valid duty notification is revoked, it will not have surplus capacity to divert its production of
 subject goods to India.
 - The submission that there exists significant freely disposable capacity in Korea is totally incorrect.

- iii. Kumho is already selling its subject goods in other countries at prices which are much higher than the export prices in India. Resultantly, with already higher prices, revocation of duty will not result in shifting of exports from other countries to India. Thus there is no likelihood of dumping of subject goods by Kumho.
- iv. Kumho has not increased its capacities since the beginning of injury period of previous investigation. Thus, the allegation of increasing capacities does not hold any merit as far as Kumho is concerned. Further, in the previous investigation, dumping margin for Kumho was determined to be a mere 1.69%. In the present investigation, the dumping margin is negative for Kumho. As a result, the allegation of continous dumping also does not hold good.

Examination by the Authority

68. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from Korea RP. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In the present investigation, as there are continued dumping of the subject goods from the subject country causing continued injury to the domestic industry, which ipso facto indicates likelihood of dumping and injury, the Authority is not required to examine whether cessation of duty is likely to lead to continued dumping and injury to the domestic industry. However, considering the fact that the dumping margin in the previous as well as the present investigation is positive and that there are favorable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reason to believe that dumping may intensify if the anti-dumping duty ceases. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject country continued to dump the subject goods in the Indian market. The following analysis would show about the likelihood of continuation/ intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty:

(i) Level of current and past dumping margin

69. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation is positive. Given the level of price undercutting and price underselling and considering the capacity in Korea RP and demand in India, the volume of dumped import is likely to increase further in the event of cessation of anti-dumping duty.

(ii)Price attractiveness of Indian market

70. The price at which the subject goods are being exported by Korea RP to India is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the current landed price in India, there is positive undercutting even with anti-dumping duty. Thus, with the cessation of anti-dumping duty, dumping is likely to intensify causing further injury to the domestic industry.

(iii) Export orientation of Korean producers

71. From the available information it is evident that the Korean producers/exporters are very much export oriented. Considering the consistent increase in the volume of imports of subject goods from the subject country during the injury period including the POI and high demand and favorable market conditions for the subject goods in Indian market, the Authority holds that if the existing anti-dumping duty is withdrawn, the entire demand for the subject goods in India can easily be catered to by the Korean exporters.

P. <u>Magnitude of Injury and injury margin</u>

72. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the Anti-dumping Rules has been compared with the landed value of the exports made by the cooperative exporters from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Particulars	UOM		POI	
		KPC	LG	All other
Non-Injurious Price (Weighted Average of Monthly NIP)	Rs/MT	***	***	***
Landed Price without ADD	Rs/MT	***	***	***
Injury Margin	Rs/MT	***	***	***
	US\$/MT	***	***	***

%	***	***	***	
Range %	10-20	10-20	10-20	

Q. Indian industry's interest and other issues

- 73. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.
- 74. The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

R. Post Disclosure Comments

- 75. The following are the post-disclosure submissions/comments made by the opposing interested parties and considered relevant by the Authority:
 - i. Inadequate time provided by the authority for offering disclosure comments.
 - ii. The present investigation was improperly and illegally initiated after the expiry of existing antidumping duties and merits termination ab-initio.
 - iii. Determination of normal value on monthly basis without taking views of Kumho is in violation of principle of natural justice.
 - iv. Duty Drawback adjustment should have been allowed by the authority to make a fair comparison between the export price and the normal value.
 - v. While calculating the normal value, the authority should have allowed the level of trade adjustment. This would have enabled authority to make a fair comparison between the export price and the normal value.
 - vi. Continuation of sunset review beyond one year is illegal and without jurisdiction. Rule 23(2) of AD Rules specifically mandates that the review shall be concluded within a period "not exceeding" twelve months from the date of initiation of such review.
 - vii. There is no correlation between domestic industry's selling price and landed value of imports. Thus, there is no link between the losses suffered by the domestic industry and the landed value of imports. Authority has failed to examine this aspect.
 - viii. Capacity with the domestic industry is insufficient to meet the demand of the Indian market. Authority has not examined this aspect properly.
 - ix. Allowing 22% return on capital employed to domestic industry while computing the non-injurious price stating is unreasonable.
 - x. The Authority has incorrectly examined depreciation cost and fixed assets. Despite declining fixed assets, there has been consistent and substantial increase in the depreciation cost.
 - xi. Authority has stated to have relied upon transaction-wise imports data provided by DGCI&S in the present investigation. But, authority has also stated that it has considered the import volume and value reported by the cooperative exporters for the POI. However, source of import data for previous years remains unknown. In view of this, the import data sourced from DGCI&S should be provided to the interested parties.
 - xii. During the POI, Russia had more than de-minimis level of imports of subject goods into India and at a price lower than the Korean import prices. Authority should examine this aspect to rule out imports from Russia and also from other countries have not caused injury to the domestic industry.
 - xiii. The transaction-wise import data of DGCI&S made available in public file shows that it includes a number of non-product under consideration as well, which should be excluded while determining the volume of imports of subject goods into India.
 - xiv. There is no link between the profits & losses of the domestic industry and the price undercutting range. During 2011-12, when the domestic industry made profits, there was a high price undercutting. However, during subsequent years, when domestic industry suffered losses, price undercutting reduced.

- xv. Authority has failed to examine that while employment level of the domestic industry has declined over the injury period, its wages has increased consistently and substantially over the same period. The undue increase in wages despite fall in employment and resultant effect of profitability of the domestic industry cannot be blamed on imports.
- xvi. As stated by the authority in other investigations, it is the endeavour of the authority not to continue anti-dumping duty beyond a period of 10 years. However, in the present review, the anti-dumping duty has been in force for more than 17 years. Authority should recommend termination of anti-dumping duty on subject goods by following its own principle.
- xvii. NBR 2255 is different from general type of NBR in terms of use of raw materials, end usage etc. authority should exclude NBR2255 from the calculation of normal value.
- xviii. While calculating normal value, Authority should include interest revenue in calculating selling, general and administrative expenses.
- xix. Authority should deduct profit from applied purchase prices of Butadiene for manufacturing cost of self-produced Butadiene.
- 76. The following are the post-disclosure submissions made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:
 - i. The exporters have resorted to excessive confidentiality while participating in the present investigations.
 - ii. The quantum of dumping margin determined is significantly low.
 - iii. Non injurious price may be determined considering actual cost where fixed expenses are apportioned on the basis of optimum production.
 - iv. The domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti dumping duty.
 - v. The anti dumping duty is required to be continued in enhanced quantum.
 - vi. Duty may be recommended on fixed amount basis in US\$ term.

Examination by the Authority

- 77. The Authority notes that the post-disclosure comments/submissions made by the interested parties are mostly reiterations and already examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of this finding. However, the post-disclosure comments/submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined as below:
 - As regards the submission that the time granted by the Authority for disclosure comments is inadequate, the Authority notes that the anti-dumping investigations are time bound and reasonable time has been granted to the interested parties for furnishing comments on the disclosure statement. In the present case, the interested parties have filed their post-disclosure comments.
 - ii. As regards the contention that present investigation was improperly and illegally initiated after the expiry of existing anti-dumping duties and merits termination ab-initio, the Authority notes that this submission has already been examined and addressed in the relevant paras of this finding. However, the Authority once again notes that the Hon'ble Delhi High Court in their Judgment has upheld the initiation as valid and legal.
 - iii. As regards the contention that determination of normal value on monthly basis without taking views of Kumho is in violation of principle of natural justice, the Authority notes that in the present investigation, apart from Kumho, there are other interested parties, who have requested for monthly analysis of dumping margin and injury margin due to wide fluctuation in the prices of NBR caused by wide variation in the prices of the major raw materials. The Authority notes that this submission has already been examined and addressed in the relevant paras of this finding. However, the Authority once again notes that in view of the wide fluctuation in the prices of NBR caused by wide variation in the prices of the major raw materials and submission made by the interested parties in this regard, the Authority considered it appropriate to undertake monthly analysis.
 - iv. As regards the submission that duty drawback adjustment should have been allowed by the authority to make a fair comparison between the export price and the normal value, the Authority notes that this claim was made by the exporters during on the spot verification. However, the exporters failed to substantiate their claim with supportive documentary evidence and demonstrate logically the linkage between the consumed materials in the exported products and the duties paid and the methodology of calculation of duty drawback. The exporters did not offer any comment on the verification reports as well. In view of this, the Authority does not consider it appropriate to accept the claim of the exporters in this regard.

- As regards the submission concerning level of trade adjustment in the normal value, the Authority notes that this claim was raised by the exporters during on the spot verification as well. The exporters had claimed level of trade adjustment on the ground that while in export sales a commission agent is involved who undertakes significant items of work and the same had been claimed as deduction from the export price, but the expenses incurred for carrying out those items of work had not been deducted from the domestic selling price. However, as already reflected in the verification reports, the company could not logically explain the claimed adjustments with supporting documentary evidence and did not offer any comment on the verification reports as well. In view of this, the Authority does not consider it appropriate to accept the claim of the exporters in this regard.
- vi. As regards the submission that continuation of sunset review beyond one year is illegal and without jurisdiction, the Authority notes that in terms of Rule 17 read with Rule 23(3) of the Antidumping Rules, the Central Government may, in its discretion in special circumstances, extend the time limit for completing the anti-dumping investigations, including review investigations, by six months beyond one year. In this regard, the Authority notes that some of the interested parties have challenged the decision of the Central Government to extend the time limit for completing the investigation for six months beyond one year before the Hon'ble Delhi High Court and the matter is pending for disposal.
- vii. As regards the submission that there is no correlation between domestic industry's selling price and landed value of imports, the authority notes that during POI, the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry even after adding anti-dumping duty, resulting in significant price undercutting.
- viii. As regards the submission that capacity of domestic industry is insufficient to meet the demand of the Indian market, the Authority reiterates that there is no legal provision mandating the domestic industry to meet the entire demand in the country in order to be eligible for protection under anti-dumping law. Moreover, imposition of anti-dumping measures does not prevent imports.
- ix. As regards the submission that allowing 22% return on capital employed to domestic industry while computing the non-injurious price is unreasonable, the Authority reiterates that granting 22% return on capital employed is a consistent practice in the DGAD.
- x. The interested parties have contended that despite declining fixed assets, there has been consistent and substantial increase in the depreciation cost. In this regard, the Authority notes that this situation is because of falling production as compared to the base year. The capacity utilization has constantly declined from 94% to 67% during POI. However, it may be noted that while calculating NIP, depreciation and other fixed costs have been taken at the highest achieved capacity utilization i.e.94% in terms of Annexure III of the Rules.
- xi. As regards the submission concerning the relied upon imports data, the Authority notes that the transaction-wise imports data provided by DGCI&S has been relied upon in the present investigation. However, for the POI, the Authority has relied upon the verified data of the cooperating exporters since the volume and value of the same was found to be higher. The transaction-wise imports data from DGCI&S source provided by the domestic industry has been made available in the public file.
- xii. As regards the submission that Authority should have taken imports of subject goods from Russia in the injury analysis as the same was more than de minimis level, the Authority notes that as per available information the Russian price is more than the Korean price.
- xiii. As regards the submission that the transaction-wise import data of DGCI&S made available in public file includes a number of non-product under consideration, the Authority notes that only volume and value of the imports of product under consideration has been taken in to account for analysis.
- xiv. As regards the submission that there is no link between the profits & losses of the domestic industry during POI, the Authority notes that during this period the domestic producer had to reduce the selling price to align it with the imported price resulting in reduction of price undercutting and increase in losses.
- xv. As regards the submission that Authority has failed to examine that the undue increase in wages despite fall in employment and resultant effect of profitability of the domestic industry, the Authority notes that the relevant injury parameters have been examined and injury to the domestic industry due to the dumped imports of subject goods from subject country has been established.
- xvi. As regards the submission that the present anti-dumping duty is in force for more than 17 years and therefore it should be discontinued, the Authority notes that there is no provision under the Customs Tariff Act or the Anti-dumping Rules or the WTO Agreement prescribing any time frame for discontinuation of anti-dumping duties. As long as there is dumping causing injury to

- the domestic industry, anti-dumping duties can be in force to provide a level playing field to the domestic industry vis-à-vis dumped goods.
- xvii. As regards the submission that NBR 2255 is different from general type of NBR and therefore the same should be excluded from the purview of the PUC, the Authority notes that the PUC in the earlier as well as present investigations is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR). The raw materials required and the production process of the various grades of the PUC is same. Moreover, the different grades of the PUC are not mutually exclusive in usage. In view of the above, the Authority does not consider it appropriate to exclude NBR 2255 from the purview of the PUC.
- xviii. As regards the submission that while calculating normal value, authority should include interest revenue in calculating selling, general and administrative expenses, the Authority notes that when a company is a multi product company and the contribution of PUC in its total sales is minimal, it is appropriate to apportion the gross interest on the basis of sales ratio.
- xix. As regards the submission that Authority should deduct profit from applied purchase prices of Butadiene for manufacturing cost of self-produced Butadiene, the Authority notes that due allowance has been given while adopting Butadiene rates for in-house production. The transfer price is comparable to that of other exporter from Korea as well.
- xx. As regards the submission of the domestic industry that the non injurious price (NIP) may be determined considering actual cost where fixed expenses are apportioned on the basis of optimum production, the Authority notes that the NIP has been determined on the basis of the provisions laid down under Annexure III of the Anti-dumping Rules.

S. CONCLUSIONS

- 78. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:
 - There is continued dumping of the product concerned from Korea RP, causing injury to the domestic industry.
 - ii) Both price undercutting and underselling are positive.
 - iii) The financial performance of the Domestic Industry has deteriorated. During the POI, the domestic industry has shown negative growth in terms of the economic parameters such as production, domestic sales, capacity utilization, market share, profit, profitability, ROCE. The dumped imports continue to cause injury to the domestic industry.
 - Dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty be withdrawn.

T. Recommendations

- 79. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be extended as specified in the duty table below.
- 80. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

DUTY TABLE

Sl. No	Heading	Description of goods	Specifi cation	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measure - ment	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	4002	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Korea RP	M/s Kumho Petrochemi cals Co Ltd	M/s Kumho Petrochemi cals Co Ltd	57	MT	US Dollar
2.	4002	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Korea RP	M/s LG Chemicals Ltd (LG)	M/s LG Chemicals Ltd (LG)	61	МТ	US Dollar
3.	4002	Acrylonitrile Butadiene Rubber	Any	Korea RP	Korea RP	Any other exporter of combination	other than	85	МТ	US Dollar

		(NBR)				exporter indicated at Sr. Nos. 1 & 2 Above				
4.	4002	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Korea RP	Any Country other than Korea RP	Any	Any	85	MT	US Dollar
5.	4002	Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)	Any	Any Country other than Korea RP	Korea RP	Any	Any	85	MT	US Dollar

U. <u>Further Procedures</u>

81. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

J. K. DADOO, Designated Authority